माननीय न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना के समक्ष

रमन **-याचिकाकर्ता**

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य **-प्रतिवादी**

2012 का सीडब्ल्यूपी नंबर 14046

जुलाई 2,2013

A. ***भारत का संविधान, 1950 - कला। 226 - मुआवजा - अत्याचारपूर्ण दायित्व - लापरवाही - विकृत दायित्व - क्या मुआवजा असाधारण मूल सिविल रिट क्षेत्राधिकार में दिया जाना चाहिए - आयोजित - क्या पीड़ित जिसके भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, क्षति की मरम्मत के लिए राज्य को बुलाया जा सकता है सिविल मुकदमे या आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से उपचार के नागरिक के अधिकार के बावजूद किया गया - रिट क्षेत्राधिकार में मौद्रिक राहत प्रदान की जा सकती है।***

अभिनिर्धारित किया गया कि मेरा मानना है कि स्वाभाविक रूप से खतरनाक चीज, जो कि प्राकृतिक रूप से बिजली है, को भागने से रोकने के लिए सभी उचित साधनों का उपयोग करने में विफलता पर, देखभाल का मानक बहुत ऊंचा होगा और आपूर्तिकर्ता पर यह दिखाने की जिम्मेदारी होगी कि कोई लापरवाही नहीं हुई है। इस मामले में, प्रतिवादी-निगम ने इस न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं किया है।

(पैरा 24)

अभिनिर्धारित किया गया कि हालांकि नीलाबती बेहरा (सुप्रा) ने हिरासत में मौत के मामले को निपटाया, लेकिन जीवन और स्वतंत्रता के लिए मौलिक प्रकाश के उल्लंघन के मामलों में "सख्त दायित्व" के आधार पर मुआवजे के पुरस्कार के सिद्धांत अन्य तथ्य स्थितियों में सार्वभौमिक अनुप्रयोग के हैं हस्तक्षेप की मांग ऐसे मामलों में जहां इस तरह का कोई तथ्यात्मक विवाद है जिसे रिट क्षेत्राधिकार में संबोधित नहीं किया जा सकता है, तो क्या याचिकाकर्ता को सिविल मुकदमे के सामान्य उपाय में डाल दिया जाना चाहिए यदि उसका मुआवजे

का दावा वास्तव में प्रकृति में विवादास्पद है जिसके लिए ऐसे अधिकारों को स्थापित करने के लिए साक्ष्य स्वीकार करने की आवश्यकता है। "सख्त दायित्व" पर आधारित अधिकारों के बीच का अंतर रिट कार्यवाही में सुधार योग्य है जहां सार्वजनिक कानून शामिल हैऔर कपटपूर्ण दायित्व को ध्यान में रखना होगा। संप्रभु प्रतिरक्षा "सख्त दायित्व" पर लागू नहीं होती है और इसका उपयोग अपकृत्य पर आधारित कार्रवाई में निजी कानून में बचाव के रूप में किया जा सकता है।

(पैरा 25)

आगे **अभिनिर्धारित किया गया कि** उपरोक्त मामले को पढ़ने पर कानून वास्तविक हो जाता हैइस मामले में मेरे मन में यह सवाल उठता है कि क्या बिजली आपूर्तिकर्ता यह दिखाकर खुद को माफ कर सकता है कि याचिकाकर्ता की चूक के कारण बिजली चोरी हुई है। हालाँकि, सख्त दायित्व से उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दों पर थोड़ा संदेह है; जानबूझकर या आश्चर्य से चोट पहुंचाने वाली संभावित खतरनाक चीज़ से बचने के सबूत का बोझ; लाइसेंसधारी से अपेक्षित देखभाल का मानक जो निर्दिष्ट तरीके से कुछ कार्यों और चीजों को करने के लिए अधिनियम और नियमों के तहत वैधानिक रूप से चौकस है; रिट क्षेत्राधिकार में उपयुक्त मामलों में मुआवजा देने और मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के संबंधित मुद्दे के लिए इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, ताकि यह न तो कम मुआवजा हो और न ही अधिक मुआवजा आदि; वर्तमान मामले में ऐसे कारक घायलों के पक्ष में हैं और हमें हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। याचिका में किया गया दावा एक कार्रवाई योग्य दावा है और यह मामला संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुआवजा देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।

(पैरा 34)

आगे **अभिनिर्धारित किया गया कि** मेरा मानना है कि सख्त दायित्व के सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जाते हैं और हमारे लोगों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए लड़ाई में युद्ध के मैदान पर आक्रमण करते हैं। भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के दृष्टिकोण से देखने पर निगम की ओर से आपराधिक लापरवाही का एक तत्व भी है।विद्युत नियम 1956 के नियम 29,44,45,46 और 91 के साथ पढ़ें, जिनके बारे में मैं कहने का साहस करता हूं कि निगम के एजेंटों और सेवकों द्वारा आवधिक या निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। 30 साल पहले सक्रिय ट्रांसमिशन लाइनें खींचने वाला निगम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकता और न ही कोई गलती का दावा कर सकता है क्योंकि निर्माण गतिविधि गांव की लाल लकीर या फिरनी से आगे तक फैल गई है। निगम का यह भी मामला नहीं है कि उसने 11 केवी ट्रांसमिशन लाइन के संचालन के तहत आने वाले क्षेत्र के निवासियों या याचिकाकर्ता के माता-पिता को मीटर के माध्यम से वैध घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं दिया है। यदि उन्होंने कनेक्शन दिया है और मीटर लगाए गए हैं और वे बिल के माध्यम से टैरिफ लेते हैं तो वे अनधिकृत निर्माण की शिकायत नहीं कर सकते। इसके अलावा, यहां तक कि यह तर्क देते हुए कि याचिकाकर्ता के पिता का संभावित रूप से आक्रामक लाइव तार को दूर रखने के लिए एंगल आयरन लगाने में हाथ था, उसे आत्म-संरक्षण

के एक कार्य के रूप में समझा जाना चाहिए, जो मनुष्य के समान ही एक आदिम प्रवृत्ति है। और जीवित रहने की उसकी सहज इच्छा। इसे आपराधिक कानून में निजी बचाव के अधिकार के समान भी देखा जा सकता है। निगम से मदद के अभाव में और खुद को और अपने परिवार को नुकसान से बचाने के लिए कोई भी उचित व्यक्ति तदनुसार कार्य कर सकता था। इसे अपने आप में मुआवज़े के उचित दावे को विफल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(पैरा 39)

B. भारत का संविधान, 1950 - कला। 226 - विद्युत अधिनियम, 2003 - धारा 68 - विद्युत नियम, 1956 - नियम 29, 44, 45, 46 और 91- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड - अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाइव बिजली ऊर्जा ले जाने के लिए हर सुर्खियों को बनाए रखना विद्युत नियम, 1956 के नियम 91 में उल्लिखित सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरण वैधानिक प्रकृति के हैं और बिजली अधिकारियों को उनके द्वारा बनाए गए लाइनों/तारों का समय-समय पर निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है ताकि आम जनता का जीवन और संपत्ति सुरक्षित रहे - बोर्ड/निगम सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह से गतिविधियों को अंजाम देना कर्तव्य है।

अभिनिर्धारित किया गया कि पहला मुद्दा जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि ट्रांसमिशन लाइनों को बनाए रखने में राज्य के प्रतिवादी निगम-लाइसेंसी पर देखभाल का कर्तव्य है जो बिजली अधिनियम, 2003 (संक्षेप में "अधिनियम" के तहत बिजली का मालिक और आपूर्तिकर्ता है)). अधिनियम की धारा 68 में लाइव विद्युत ऊर्जा ले जाने वाली ओवरहेड लाइनों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान यह निर्धारित करता है कि अधिनियम की धारा 68(2) के प्रावधानों के अनुसार, एक ओवरहेड लाइन, उपयुक्त सरकार की मंजूरी के साथ, जमीन के ऊपर स्थापित या स्थापित रखी जाएगी। धारा 68 जिला मजिस्ट्रेट को ओवरहेड लाइन के पास के पेड़ों, संरचनाओं या वस्तुओं को हटाने का अधिकार देती है। विद्युत बोर्ड/निगम को चालू विद्युत लाइनों के रखरखाव के लिए हर समय सतर्क रहना चाहिए।

(पैरा 18)

आगे **अभिनिर्धारित किया गया कि** विद्युत नियम 1956 का नियम 91 (संक्षेप में "नियम") किसी सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान या किसी उपभोक्ता के परिसर के किसी भी हिस्से पर खड़ी ओवरहेड विद्युत लाइनों की सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरणों की प्रक्रिया निर्धारित करता है और यह आदेश देता है कि वे होंगे लाइन टूटने की स्थिति में लाइन को विद्युत रूप से हानिरहित बनाने के लिए निरीक्षक द्वारा अनुमोदित उपकरण से संरक्षित किया गया है।

(पैरा 19)

आगे **अभिनिर्धारित किया गया कि** विद्युत नियम 1956 के नियम 29,44,45 और 46 वैधानिक प्रकृति के हैं और बिजली अधिकारियों को उनके द्वारा बनाए गए लाइनों का समय-समय पर निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है और दुर्घटना को रोकने और लाइनों को बनाए रखने के लिए ऐसे सभी सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता होती है। इस तरह से कि आम जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जा सके। बोर्ड/निगम इस तरह से गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बाध्य है कि सुरक्षा और सुरक्षा प्रावधानों को वैधानिक नियमों के अनुसार लागू किया जाए।

(पैरा 20)

आगे **अभिनिर्धारित किया गया कि** विनफील्ड और जोलोविज़ के 11वें संस्करण मेंस्वीट और मैक्सवेल द्वारा टॉर्ट, इसे विद्वान लेखकों द्वारा पृष्ठ 352 और पृष्ठ 889 पर निम्नानुसार देखा गया है: -

> "बिजली, एक खतरनाक चीज़ है और परिणामस्वरूप कर्तव्य हैरायलैंड्स बनाम फ्लेचर ((1868) एलआर 3 एचएल 330) में यह कहा गया है कि जो लोग इसके मालिक हैं या इसे नियंत्रित करते हैं। बिजली के लिए दायित्व बिल्कुल गैस के समान ही है। "बिजली के लिए दायित्व गैस के समान ही है। यह निर्णय लिया गया है कि रायलैंड्स बनाम फ्लेचर ((1868) एलआर 3 एचएल 330) का सिद्धांत बिजली पर लागू होता है, और इसके परिणामस्वरूप तारों या केबलों के मालिक जिनके माध्यम से विद्युत प्रवाह होता है गुजरने से उन्हें अपने जोखिम पर अहानिकर रहना चाहिए।"

(पैरा 32)

> ***सी। भारत का संविधान, 1950 - कला। 226- मुआवज़ा*** रिट क्षेत्राधिकार में - मुआवजे की मात्रा का आकलन - ओवरहेड लाइनों/तारों से नाबालिग बच्चे की करंट लगने से मौत के कारण मुआवजा मांगा गया - 4 साल की उम्र के नाबालिग बच्चे को स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा - विशेष विशिष्ट तथ्यों में मुआवजे की मात्रा का निर्धारण किसी भी सीधे जैकेट फॉर्मूले के अधीन नहीं किया जा सकता है - मल्टीप्लायर सिस्टम पर आधारित फॉर्मूला मुआवजा तय करने का आधार नहीं हो सकता.

अभिनिर्धारित किया गया कि कानूनी मसले सुलझ गए हैं, कोर्ट की एकमात्र चिंता यह है कि इस आसानी में किस हद तक राहत दी जाए। एक ऐसे नाबालिग की सहजता के लिए किन मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए जिसका भविष्य ही अंधकारमय और अनिश्चितता से भरा हुआ छोड़ दिया गया है? आय की हानि, संपत्ति की हानि, भविष्य में रोजगार की संभावना आदि के सिद्धांत एक नाबालिग बच्चे की सहजता में अमूर्त रहते हैं।

(पैरा 35)

आगे **अभिनिर्धारित किया गया कि** चूंकि वर्तमान में कोई मोटर दुर्घटना सुगमता नहीं है, इसलिए इस सहजता के विशेष और विशिष्ट तथ्यों में मुआवजे की मात्रा का निर्धारण किसी सीधे जैकेट फार्मूले के अधीन नहीं किया जा सकता है। गुणक/गुणक प्रणाली पर आधारित सूत्र इस आसानी में न्यायालय का मार्गदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन मोटर दुर्घटनाओं में न्यायालयों द्वारा विकसित मुआवजे के व्यापक और अंतर्निहित सिद्धांत न्यायालय के लिए मार्गदर्शन बने रहेंगे। इलेक्ट्रोक्यूशन के मामलों में, न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मुआवजा दे सकता है। हालाँकि, जिन विभिन्न शीर्षों के तहत मुआवजा दिया जा सकता है, वे मोटे तौर पर न्यायिक मिसालों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिनमें मोटर दुर्घटना में मृत्यु या चोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में या बिजली के संपर्क के कारण बिजली के झटके के मामले में मुआवजे का पुरस्कार शामिल है। तार और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें।

(पैरा 38)

आगे **अभिनिर्धारित किया गया कि** मैं श्री मल्होत्रा से सहमत हूं कि बिजली के झटके से हुई चोट की भयावहता के मामले में यह एक अनोखा और अनोखा मामला है, जिसके तहत विशेष मुआवजा और क्षति देने का यह एक बेहद उपयुक्त तरीका है।

(पैरा 39)

आगे **अभिनिर्धारित किया गया कि** मुझे लगता है कि केवल एक पर्याप्त मौद्रिक शुरुआत ही वर्तमान और भविष्य में शारीरिक विकलांगता की विशालता को बेहतर ढंग से पूरा कर सकती है। यदि वर्तमान में इस न्यायालय के हस्तक्षेप से याचिकाकर्ता का ध्यान नहीं रखा गया तो उसे वास्तव में कभी भी उचित मुआवजा नहीं दिया जा सकेगा। यदि याचिकाकर्ता को निगम के विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए मुकदमे के नागरिक उपचार से वंचित कर दिया जाता है, तो वह अकेले देरी से बर्बाद हो जाएगा।

(पैरा 40)

याचिकाकर्ता की ओर से राहुल जसवाल, विवेक के.ठाकुर, अधिवक्ता

तनीषा पेशावरिया, डीएजी हरियाणा

केएस मलिक, प्रतिवादी क्रमांक 2 से 4 के वकील

अनिल मल्होत्रा, न्याय मित्र

राजीव नारायण रैना, जे.

(1) करंट लगने से हुई एक दुखद और हृदय विदारक दुर्घटना में चार साल का बच्चा रमन गांव सनौली खुर्द, जिला पानीपत में अपने पिता के मकान की छत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी ट्रांसमिशन लाइन के संपर्क में आने से झुलस गया। परिणाम स्वरूप अंगों का तीन बार विच्छेदन, एक दुर्लभ स्थिति, जो 100% स्थायी विकलांगता से भी बदतर स्थिति का कारण बनती है।

(2) घायल रमन ने अपने पिता, मनोज कुमार के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की है, जिसमें उत्तरदाताओं-उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (संक्षेप में "निगम") और हरियाणा राज्य से दोनों हथियारों के नुकसान के लिए मुआवजे का दावा किया गया है। बायां पैर कम उम्र में ही कट गया, जिससे भविष्य में कमाई करने और अपना भरण-पोषण करने के लगभग सभी रास्ते बंद हो गए और साथ ही बड़े होकर मर्दानगी हासिल करने और बच्चों द्वारा किए जाने वाले सामान्य काम करने की छोटी-छोटी खुशियों से भी वंचित कर दिया गया और छोड़ दिया गया। जब तक वह जीवित है, तब तक पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर जीवन का सामना करता है। हो सकता है कि उसे कभी दुल्हन न मिले या वह परिवार शुरू न कर पाए। जब तक आधुनिक विज्ञान की जादुई दुनिया अप्रत्याशित कीमत पर कृत्रिम अंगों, रोबोटिक्स और भविष्य की स्टेम सेल तकनीक के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं करती, तब तक वह कभी भी शाब्दिक और रूपक रूप से अपना पेट भरने में सक्षम नहीं हो सकता है। पुरानी कहावत है - भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं - लेकिन यह इस मामले में उपयुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि यह न्यायालय असहाय, दलित, विकलांग और अशक्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अस्तित्व में है, जिन्हें भाग्य ने त्याग दिया है। याचिकाकर्ता की दुर्दशा की भयावहता को देखने और समझने के लिए उसकी तस्वीरें इस बात का सबसे अच्छा सबूत हैं कि उसके पास क्या बचा है और जिन्हें परिशिष्ट 1 के रूप में आदेश का हिस्सा बनाया गया है।

(3) याचिका पर इस न्यायालय द्वारा 26.7.2012 को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था। निगम ने लिखित बयान दाखिल कर मामले का विरोध किया है। 3.11.2011 को बिजली के झटके से लगी चोट पर विवाद नहीं किया गया हैबच्चा याचिकाकर्ता के पिता द्वारा गांव सनोली खुर्द, जिला पानीपत में बनाए गए घर की छत के ऊपर से गुजर रहे 11 केवी के नंगे तार के संपर्क में आ गया, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता है। यह बताया गया है कि 11 केवी ट्रांसमिशन लाइन तीन दशक पहले कृषि क्षेत्रों के ऊपर से गुजरी और स्थापित की गई थी। समय के साथ, जैसा कि ऐतिहासिक आवश्यकता है, गांव की आबादी देह या लाई लकीर के बाहर कई निर्माण हुए हैं, जहां याचिकाकर्ता के पिता ने लगभग एक दशक पहले अपने परिवार के लिए एक घर बनाया था, जहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी।

(4) याचिकाकर्ता के घर के ऊपर से एक बिजली के खंभे से दूसरे तक गुजरने वाली बिजली पारेषण लाइनों के समूह में से एक छत के एक कोने के करीब खतरनाक रूप से लटका हुआ है। इसे पकड़ने और नुकसान के रास्ते से दूर रखने के लिए इसे एंगल आयरन पर एक इंसुलेटर स्थापित किया गया है। स्थिति को समझने के लिए एंगल आयरन के साथ इंसुलेटर की तस्वीर से बेहतर कुछ नहीं होगा, जो इस आदेश के साथ परिशिष्ट 2 के रूप में संलग्न है।

(5) याचिकाकर्ता के पिता का घर एक दुकान-सह-निवास है जहां वह अपना स्पेयर पार्ट व्यवसाय करते हैं। यह घर बड़ी संख्या में आवासों के बीच स्थित है, जो स्पष्ट रूप से कानूनी मंजूरी या किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना या बिजली विभाग-निगम-बिजली निगम के प्रतिवादी को सूचित करने से पहले बनाए गए हैं, कि गुजरने वाले तार समय से बहुत पहले खींचे जाने पर आदमी को घायल कर सकते हैं। प्रभावित परिवार का जमीन पर आना।

(6) एसडीओ (ऑपरेशंस) सब डिवीजन, यूएचबीवीएनएल, छाजपुर, जिला पानीपत द्वारा दायर लिखित बयान में यह स्पष्ट किया गया है कि तस्वीर में देखा गया इंसुलेटर/एंगल आयरन (याचिका का पी-4 और इस आदेश का परिशिष्ट 2) नहीं था। बिजली विभाग के किसी कर्मचारी द्वारा लगाया गया। याचिकाकर्ता के पिता पर सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने घर की छत के किनारे हाई-टेंशन तार से बचने के लिए खुद इंसुलेटर लगाया ताकि ईंट और गारे को न छूएं। इसलिए, विभाग या उसके एजेंटों और नौकरों की ओर से अपने कर्तव्यों के पालन में कोई लापरवाही नहीं हुई है, और इसलिए, न तो निगम और न ही उसके कर्मचारियों को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार या जवाबदेह ठहराया जा सकता है, क्षति या मौद्रिक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मुआवज़ा।

(7) जब यह मामला 10.1.2013 को सुनवाई के लिए आया, तो इस न्यायालय ने इस न्यायालय के एक वकील श्री अनिल मल्होत्रा से कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दों पर न्याय मित्र के रूप में सहायता करने का अनुरोध किया, जिसमें कपटपूर्ण दायित्व के मामलों से जुड़े कानूनी सिद्धांतों के बहुत अधिक शोध की आवश्यकता होती है। , लापरवाही, प्रतिवर्ती दायित्व, इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न वैधानिक और सख्त दायित्व जहां लापरवाही से इनकार किया गया था, और मुआवजे की मात्रा के आकलन पर इसका कुल प्रभाव जो असाधारण मूल नागरिक में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दिया जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है। इस कार्य को श्री मल्होत्रा ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया और फिर उनसे अनुरोध किया गया कि वे रिट कार्यवाही में मुआवजे के पुरस्कार से जुड़े उदाहरणों और भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 में पाए गए वैधानिक प्रावधानों से जुड़े कानूनी सिद्धांतों के आलोक में अदालत की सहायता करें। संक्षेप में "अधिनियम")। याचिकाकर्ता के युवा विद्वान वकील श्री राहुल जयसवाल ने मामले की तैयारी में श्री मल्होत्रा की मदद करने के लिए इस पद को खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया।

(8) विद्वान एमिकस क्यूरी ने अपने परिश्रम के फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के अनेक निर्णयों को रिकॉर्ड पर रखा है और किसी भी पक्ष की ओर से स्वयं को प्रस्तुत किए बिना इस न्यायालय के विचार हेतु ज्ञानवर्धक लिखित प्रस्तुतियाँ भी दाखिल की हैं। उसका मौखिक पता. उस सामग्री का विज्ञापन करने से पहले, मामले को आगे बढ़ाने के लिए तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का विज्ञापन करना आवश्यक हो सकता है।

(9) घायल लड़के, रमन को 3.11.2011 को बिजली का करंट लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद दुर्भाग्य से जोड़ों से थोड़ा आगे तक उसके तीन अंग काटने पड़े। उसी दिन पुलिस चौकी सनौली खुर्द, पानीपत के रपट रोजनामचा में क्रम संख्या 15 पर एक दैनिक डायरी प्रविष्टि दर्ज की गई थी। लड़के को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय आरएम आनंद अस्पताल, पानीपत ले जाया गया, जहां से मामले को पीजीआईएमएस, रोहतक रेफर कर दिया गया। अंतिम उपचार नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में किया गया, जहां डॉक्टरों के पास एक साथ तीन अंग काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, जिससे रमन अपंग हो गया।

(10) याचिकाकर्ता के पिता ने 9.1.2012 को एएसआई ओम प्रकाश के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस चौकी का दौरा किया, जिन्होंने पहले घटनास्थल का दौरा किया था और उनके सामने बताया था कि उनका चार साल का बेटा गलती से वहां से गुजर रहे हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गया था। उसकी इमारत की छत पर. बताया गया कि पीड़िता का इलाज पीजीआईएमएस, रोहतक से नई दिल्ली के सफदाइजंग अस्पताल में कराया गया। पुलिस ने डेली रिकार्ड किया9.1.2012 को मनोज कुमार के बयान पर पुलिस चौकी सनौली खुर्द, पानीपत में डायरी एंट्री नंबर 7। 19.9.2012 को, एसएसपी, पानीपत ने डीएसपी, मुख्यालय, पानीपत को मामले की जांच करने और घटनास्थल पर जाकर और अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से व्यक्तियों के बयान आदि दर्ज करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अधिकारी, डीएसपी मुख्यालय, पानीपत ने पीड़ित के पिता मनोज कुमार, सहायक फोरमैन लाल चंद, सहायक लाइनमैन साहिब सिंह, लाइनमैन रामेश्वर, और छाजपुर, पानीपत में यूएचबीवीएन के उपमंडल अधिकारी शशि कुमार का बयान दर्ज किया। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि शिकायत केंद्र, सनौली खुर्द, पानीपत या एसडीएम, छाजपुर के कार्यालय में याचिकाकर्ता के पिता या किसी अन्य व्यक्ति से 11 केवी हाईटेंशन तारों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। बताया गया कि 11 केवी हाई टेंशन बिजली लाइनें लगभग 30-32 साल पहले कृषि क्षेत्रों के ऊपर से गुजरी थीं, जहां एक दशक पहले मनोज कुमार ने अन्य इमारतों के बीच अपना घर बनाया था। पुलिस जांच से पता चला कि बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा इंसुलेटर नहीं लगाया गया था, और इसलिए, उन्हें 3.11.2011 को हुई दुर्घटना के संबंध में अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाह नहीं पाया गया।

(11) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली द्वारा जारी डिस्चार्ज सारांश की फोटोकॉपी से पता चलेगा कि उपस्थित चिकित्सक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया दोनों ऊपरी अंगों के विच्छेदन और स्टंप कटौती द्वारा की गई थी। चूँकि लगी चोटें इलाज योग्य नहीं थीं, दोनों ऊपरी बांहों और बाएं पैर में गैंग्रीन की उपस्थिति होने पर तीन बार अंग विच्छेदन करना पड़ा।

बिजली से जलने की चोटों के इलाज के लिए रमन 28.12.2011 से 31.12.2011 तक सफदरजंग अस्पताल में एक इनडोर मरीज रहे। दलील दी गई है कि रमन को 3.11.2011 को ही आरएम आनंद अस्पताल, पानीपत द्वारा पीजी1एमएस, रोहतक रेफर कर दिया गया था। बच्चे को सिविल सर्जन कार्यालय, पानीपत द्वारा दिनांक 8.2.2012 को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें उसकी विकलांगता को चिकित्सकीय रूप से शत-प्रतिशत प्रमाणित किया गया है।

(12) अपकृत्य में लापरवाही के सवाल पर लाइसेंसधारी ने जोरदार विवाद किया है, क्योंकि वह इस बात से इनकार करता है कि उसका घटना से कोई लेना-देना है या उसके एजेंटों के किसी भी कार्य या चूक से किसी भी अप्रत्यक्ष दायित्व का कोई लेना-देना नहीं है। स्पष्ट रूप से कहें तो, प्रतिवादी निगम के विद्वान वकील श्री केएस मलिक का कहना है कि जिस मानव हाथ ने संभावित खतरनाक तार को घर की छत के संपर्क में आने से रोकने के लिए कंडक्टर को लोहे के एंगल पर रखा था, वह उनका नहीं था।

(13) याचिकाकर्ता के पिता ने रिट याचिका के पैराग्राफ 10 में दावा किया है कि उन्होंने दुर्घटना होने से पहले 16.8.2011 को एक अभ्यावेदन के माध्यम से एसडीओ, सब डिवीजन, छाजपुर, पानीपत- प्रतिवादी संख्या 4 से संपर्क किया और उनसे कोण को हटाने का अनुरोध किया। मकान की छत गिरा दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस अभ्यावेदन की एक सच्ची अनुवादित प्रति अनुलग्नक पी-3 के रूप में रिकॉर्ड में रखी गई है और इसकी मूल की फोटोकॉपी डॉकेट में पाई गई है। इस पर मनोज कुमार और कुछ अन्य निवासियों ने भी हस्ताक्षर किये हैं. रिट याचिका के पैराग्राफ 10 की सामग्री का निगम, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा आम लिखित बयान में खंडन किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने घर से लोहे के एंगल को हटाने के लिए कभी भी एसडीओ से संपर्क नहीं किया और न ही ग्राम सनौली खुर्द के शिकायत केंद्र पर ऐसा कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। रिट याचिका के पैराग्राफ 10 की सामग्री और लिखित बयान में उसके संबंधित पैराग्राफ को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि दिनांक 16.8.2011 के प्रतिनिधित्व के अस्तित्व या प्रस्तुतिकरण का कोई विशेष खंडन नहीं है। बताया जाता है कि ग्राम सनौली खुर्द के शिकायत केंद्र पर ऐसा कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ। याचिकाकर्ता का यह दावा नहीं है कि उसने शिकायत केंद्र में अभ्यावेदन छोड़ दिया था। वास्तव में दावा यह है कि उसने दुर्घटना से पहले प्रतिनिधित्व के माध्यम से चौथे प्रतिवादी से संपर्क किया था, जो तथ्य का दावा रिकॉर्ड पर अप्रकाशित है। इसलिए, रिट याचिका के पैराग्राफ 10 और उसकी प्रतिक्रिया को लिखित बयान में पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक होगा: -

> *रिट याचिका का पैराग्राफ 10:- "याचिकाकर्ता ने दुर्घटना से पहले छत से लोहे के एंगल को हटाने के लिए एसडीओ, सब डिवीजन, छाजपुर, पानीपत यानी प्रतिवादी नंबर 4 से दिनांक 16.8.2011 को अभ्यावेदन के माध्यम से संपर्क किया था। सदन लेकिन प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिनांक 16.8.2011 के अभ्यावेदन की एक प्रति इसके साथ अनुबंध पी-3 के रूप में संलग्न है।"*

*उत्तरदाताओं संख्या 2 से 4 के लिखित बयान के अनुच्छेद 10: - "रिट याचिका के अनुच्छेद संख्या 10 की सामग्री गलत है और इस तरह से इनकार किया गया है। इसके उत्तर में यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने कभी भी एसडीओ यानी प्रतिवादी से संपर्क नहीं किया क्रमांक 4 अथवा निगम के किसी अन्य अधिकारी द्वारा उनके घर से लोहे के एंगल हटाने हेतु न ही ग्राम सनौली खुर्द के शिकायत केन्द्र पर ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। यह आगे है*निगम के सेल सर्कुलर के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान से बिजली का तार हटाना चाहता है तो उसे शपथ पत्र के साथ आवेदन देना होगा तथा अनुमानित खर्च भी संबंधित एसडीओ के कार्यालय में जमा कराना होगा।

(14) इस न्यायालय के दिनांक 2.3.2013 के आदेश के जवाब में याचिकाकर्ता के पिता, मनोज कुमार द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे में उन्होंने हलफनामे के पैराग्राफ 6 में अंडरसीआर के रूप में दावा किया है: -

"6. अभिसाक्षी ने प्रस्तुत किया कि घर की छत पर लोहे का एंगल, जहां से 11 केवी हाई पावर टेंशन लाइन गुजरती है, वर्ष 2006 में बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा लगाया गया था।

(15) इस न्यायालय ने 2.3.2013 को निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने पीड़िता की जन्मतिथि, परिवार की स्थिति, घायल के पिता की वकालत का खुलासा करते हुए याचिकाकर्ता का एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने की प्रार्थना की; क्या बच्चे की माँ कार्यरत है; भाई-बहनों की संख्या और उनकी उम्र और उनके द्वारा पढ़े गए स्कूल, यदि कोई हो। हलफनामे में कुल पारिवारिक आय यानी माता-पिता की संयुक्त आय का खुलासा होना चाहिए, न कि उनके भाई-बहनों आदि की; उस भवन के निर्माण की तारीख जहां बच्चे को करंट लगा था; क्या माता-पिता मालिक हैं या किरायेदार; क्या भवन आबादी देह गांव के लाल डोरे के भीतर है; यदि लाई डोरा के बाहर, तो क्या ग्राम पंचायत की एनओसी प्राप्त की गई थी; घर की छत पर जहां से 11 केवी हाई पावर टेंशन लाइन गुजरती है, एंगल आयरन किसने लगाया; एंगल का लोहा कब और किसने स्थापित किया था; निर्माण के घनत्व से पता चलता है कि संबंधित घर के तत्काल पड़ोस में कितने घर एलएल केवी हाई पावर टेंशन लाइन के नीचे आते हैं; साइट पर प्राप्त स्थिति को दर्शाने वाली तस्वीरें भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

सुश्री पेशावरिया, पीड़ित मुआवजे के संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा प्रख्यापित आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जे973 की धारा 357-ए के तहत बनाई गई योजना, यदि कोई हो, के संबंध में निर्देश मांगेंगी। वह बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत किए गए किसी भी कार्य के बारे में एसडीएम/कार्यकारी

मजिस्ट्रेट, पानीपत को एक हलफनामा भी दाखिल करेंगी। हलफनामे में यह भी बताया जाएगा कि क्या जिस निर्माण पर बच्चा घायल हुआ था वह एक अधिकृत कॉलोनी है और क्या निर्माण योजनाएं ग्राम पंचायत गांव सनोली खुर्द, पानीपत सहित किसी भी प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई हैं। हलफनामे में यह भी बताया जाएगा कि भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 91 या हरियाणा में संचालित किसी भी काउंटर-पार्ट नियमों के अनुपालन में उक्त गांव में सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरणों के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। .

निगम की ओर से उपस्थित श्री मलिक ने भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में प्रतिवादी-निगम द्वारा उठाए गए कदमों और उसके तहत बनाए गए नियमों और उठाए गए कदमों की रूपरेखा बताते हुए अधिक विस्तृत और व्यापक हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। अपने अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ओवरहेड लाइनों को सुरक्षित बनाने के वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में ताकि वे जीवन को खतरे में न डालें और लिखित बयान में औचित्य पर बोलें कि लाइनें 30 या 32 साल पहले बिछाई गई थीं, इस प्रकार जमीन पर जिम्मेदारी से भागना लाल डोरा के बाहर और आबादी से गुजरने वाली 11 केवी हाई पावर टेंशन लाइन के नीचे बस्तियां विकसित हो गई हैं।

प्रतिवादी के वकील के अनुरोध के अनुसार चार सप्ताह के भीतर उपरोक्त का उत्तर दिया जाए। सूची दिनांक 02.04.2013. ”

(16) इसी आदेश के प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता के पिता ने दिनांक 30.3.2013 को उपरोक्त शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने निम्नलिखित तथ्यों की शपथ ली है:-

1. यह कि अभिसाक्षी के पुत्र रमन कुमार पुत्र मनोज कुमार का जन्म 10.9.2007 को हुआ था और अभिसाक्षी के दो बच्चे हैं जिनके नाम रमन कुमार लड़का और लड़की खुशी है।

2. यह कि अभिसाक्षी परिवार में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति है क्योंकि उसकी पत्नी एक गृहिणी है और दो बच्चे हैं, एक घायल रमन है और दूसरी लड़की ख़ुशी है जो सनौली खुर्द के सरस्वती शिक्षा मंदिर में चौथी कक्षा में पढ़ती है।

3. यह कि अभिसाक्षी की गाँव में स्पेयर-पार्ट की दुकान है और उसके परिवार की संयुक्त आय लगभग 35,000 प्रति वर्ष है।

4. जिस इमारत में बच्चे को करंट लगा, उसका निर्माण वर्ष 2000 में हुआ था और गवाह उसका मालिक है, क्योंकि उसने लगभग 30 गज जमीन खरीदी थी।

5. यह भवन गांव आबादी देह के लाल डोरा के बाहर है और ग्राम पंचायत से एनओसी नहीं ली गई है क्योंकि गांवों में एनओसी नहीं दी जाती है या ली जाती है।

6. <u>अभिसाक्षी ने प्रस्तुत किया कि घर की छत पर जहां से एचकेवी हाई पावर टेंशन लाइन गुजरती है, लोहे का एंगल वर्ष 2006 में बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा लगाया गया था।</u>

7. कि अभिसाक्षी का घर कम से कम 40 से 60 घरों से घिरा हुआ है और यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है और सभी घर एचकेवी हाई पावर टेंशन लाइन के नीचे या उसके पास पड़ते हैं। साइट की वास्तविक स्थिति दिखाने वाली तस्वीरें संलग्न हैं।"

(17) इस हलफनामे का कोई खंडन नहीं है, हालांकि पैराग्राफ 6 में सामग्री और सत्यापन योग्य विवरण शामिल हैं। किसी भी आधार पर इसे त्यागने का कोई कारण नहीं है, स्वार्थी होने के आधार पर तो दूर। जब याचिकाकर्ता के संस्करण को गैर-पारगमन के आधार पर स्वीकार किया जाता है तो मामला लापरवाही के दायरे में आता है और इसलिए, सख्त दायित्व के अलावा कपटपूर्ण दायित्व भी होता है।

(18) विचार के लिए उठने वाला पहला मुद्दा राज्य के प्रतिवादी निगम-लाइसेंसी पर ट्रांसमिशन लाइनों के रखरखाव में देखभाल का कर्तव्य है, जो बिजली अधिनियम, 2003 (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत बिजली का मालिक और आपूर्तिकर्ता है। . अधिनियम की धारा 68 में लाइव विद्युत ऊर्जा ले जाने वाली ओवरहेड लाइनों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान यह निर्धारित करता है कि अधिनियम की धारा 68(2) के प्रावधानों के अनुसार, एक ओवरहेड लाइन, उपयुक्त सरकार की मंजूरी के साथ, जमीन के ऊपर स्थापित या स्थापित रखी जाएगी। धारा 68 जिला मजिस्ट्रेट को ओवरहेड लाइन के पास के पेड़ों, संरचनाओं या वस्तुओं को हटाने का अधिकार देती है। विद्युत बोर्ड/निगम को चालू विद्युत लाइनों के रखरखाव के लिए हर समय सतर्क रहना चाहिए। अधिनियम की धारा 68 इस प्रकार है

"68.(1) एक ओवरहेड लाइन, उपयुक्त सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार जमीन के ऊपर स्थापित या स्थापित रखी जाएगी।

2. उपधारा (1) में निहित प्रावधान लागू नहीं होंगे-

(a) एक विद्युत लाइन के संबंध में जिसका नाममात्र वोल्टेज 11 किलोवोल्ट से अधिक नहीं है और जिसका उपयोग एकल उपभोक्ता को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है या करने का इरादा है;

(b) विद्युत लाइन के उतने हिस्से के संबंध में जो इसकी स्थापना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में परिसर के भीतर है या होगा; या

(c) ऐसे अन्य मामलों में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(3) *उपयुक्त सरकार, उप-धारा (1) के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय, ऐसी शर्तें लगाएगी (लाइन के स्वामित्व और संचालन की शर्तों सहित) जो उसे आवश्यक लगे*

(4) *उपयुक्त सरकार उसके द्वारा दी गई मंजूरी में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय मंजूरी में बदलाव कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है।*

(5) *जहां कोई पेड़ ओवरहेड लाइन के पास खड़ा या पड़ा हुआ है या जहां कोई संरचना या अन्य वस्तु जो ऐसी लाइन लगाने के बाद ओवरहेड लाइन के पास रखी गई है या गिर गई है, उसमें बाधा उत्पन्न करती है या हस्तक्षेप करती है, या बाधा डालने या हस्तक्षेप करने की संभावना है, परिवहन या*बिजली के संचरण या बिजली के परिवहन या संचरण या किसी भी कार्य की पहुंच में बाधा डालने या हस्तक्षेप करने के लिए, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी, लाइसेंसधारी के आवेदन पर, पेड़, संरचना या वस्तु का कारण बन सकता है। जिसे वह उचित समझे, हटा दिया जाए या अन्यथा निपटा दिया जाए।

(6) *उप-धारा (5) के तहत एक आवेदन का निपटान करते समय, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या उस उप-धारा के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी, ओवरहेड लाइन लगाने से पहले अस्तित्व में किसी भी पेड़ के मामले में, पेड़ में रुचि रखने वाले व्यक्ति को पुरस्कार देगा। ऐसा मुआवजा जिसे वह उचित समझे, और ऐसा व्यक्ति उसे लाइसेंसधारी से वसूल कर सकता है।*

स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "पेड़" में कोई झाड़ी, बाड़, जंगल का विकास या अन्य पौधा शामिल माना जाएगा।"

(19) विद्युत नियम 1956 का नियम 91 (संक्षेप में "नियम") सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान या किसी उपभोक्ता के परिसर के किसी भी हिस्से पर खड़ी ओवरहेड विद्युत लाइनों की सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरणों की प्रक्रिया निर्धारित करता है और यह आदेश देता है कि उन्हें संरक्षित किया जाएगा। लाइन टूटने की स्थिति में लाइन को विद्युत रूप से हानिरहित बनाने के लिए निरीक्षक द्वारा अनुमोदित उपकरण के साथ। ये सुरक्षा उपाय वैधानिक रूप से विद्युत अधिकारियों द्वारा प्रदान किए जाने आवश्यक हैं। नियम 91 इस प्रकार है:-

"91. सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरण: - (1) सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान के किसी भी हिस्से पर खड़ी की गई प्रत्येक ओवरहेड लाइन, (जो मृत बियरर तार से निलंबित नहीं की गई है और इन्सुलेशन सामग्री से ढकी नहीं हुई है और ट्रॉली-तार नहीं है) या किसी कारखाने या खदान में या किसी उपभोक्ता के परिसर में लाइन टूटने की स्थिति में विद्युतीय रूप से हानिरहित बनाने के लिए निरीक्षक द्वारा अनुमोदित

उपकरण से संरक्षित किया जाएगा।

(2) एक इंस्पेक्टर लिखित नोटिस देकर ऐसी किसी भी ओवरहेड लाइन के मालिक से, जहां भी इसे बनाया जा सकता है, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट तरीके से इसकी सुरक्षा करने की मांग कर सकता है।

(3) प्रत्येक उच्च और अतिरिक्त-उच्च वोल्टेज ओवरहेड लाइन का मालिक अनधिकृत व्यक्तियों को ऐसी ओवरहेड लाइनों के किसी भी समर्थन पर चढ़ने से रोकने के लिए निरीक्षक की संतुष्टि के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा, जिस पर सीढ़ी या विशेष की मदद के बिना आसानी से चढ़ा जा सकता है। उपकरण। इस नियम के प्रयोजन के लिए रेल, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट खंभे और बिना सीढ़ियों वाले पूर्व-तनावग्रस्त सीमेंट कंक्रीट खंभे, ट्यूबलर खंभे, बिना सीढ़ियों वाले लकड़ी के समर्थन, /- सेक्शन और चैनल को समर्थन माना जाएगा जिन पर आसानी से नहीं चढ़ा जा सकता है] ।

(20) विद्युत नियम 1956 के नियम 29, 44, 45 और 46 वैधानिक प्रकृति के हैं और बिजली अधिकारियों को उनके द्वारा बनाए गए लाइनों का समय-समय पर निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है और दुर्घटना को रोकने और लाइनों को बनाए रखने के लिए ऐसे सभी सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता होती है। जिससे आम जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जा सके। बोर्ड/निगम गतिविधियों को इस तरह से संचालित करने के लिए बाध्य है कि सुरक्षा और सुरक्षा प्रावधान वैधानिक नियमों के अनुसार लागू किए जाएं। उपरोक्त नियम त्वरित संदर्भ के लिए पुन: प्रस्तुत किए गए हैं: -

"29. विद्युत आपूर्ति लाइनों और उपकरणों का निर्माण, स्थापना, सुरक्षा, संचालन और रखरखाव। - (जे) सभी विद्युत आपूर्ति लाइनें और उपकरण बिजली, इन्सुलेशन और अनुमानित दोष वर्तमान और पर्याप्त यांत्रिक शक्ति के लिए पर्याप्त रेटिंग के होंगे। कर्तव्य जो उन्हें स्थापना की पर्यावरणीय स्थितियों के तहत करने की आवश्यकता हो सकती है, और इस तरह से निर्माण, स्थापित, संरक्षित, काम और रखरखाव किया जाएगा ताकि मानव, जानवरों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके],

(2) इन नियमों में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, इस नियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए [भारतीय मानक ब्यूरो] [राष्ट्रीय विद्युत संहिता सहित] की प्रासंगिक अभ्यास संहिता का पालन किया जा सकता है और किसी भी असंगतता की स्थिति में इन प्रावधानों का पालन किया जा सकता है। नियम प्रबल होंगे.

(3) उपयोग की जाने वाली सामग्री और उपकरण [भारतीय मानक ब्यूरो] के प्रासंगिक विनिर्देशों के अनुरूप होंगे जहां ऐसे विनिर्देश पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं।

xxxxx----xxxxx----xxxx

(44) बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्तियों की बहाली के लिए निर्देश.- (1) बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्तियों की बहाली के लिए अंग्रेजी या हिंदी और जिले की स्थानीय भाषा में निर्देश, और जहां हिंदी स्थानीय भाषा है, वहां अंग्रेजी और हिंदी में निर्देश दिए जाएंगे. कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (एम) में परिभाषित अनुसार प्रत्येक उत्पादन स्टेशन, संलग्न उप-स्टेशन, संलग्न स्विच-स्टेशन और प्रत्येक कारखाने में एक विशिष्ट स्थान पर मालिक द्वारा चिपकाया जाएगा। का उपयोग किया जाता है और ऐसे अन्य परिसरों में जहां बिजली का उपयोग किया जाता है, निरीक्षक या निरीक्षक की सहायता के लिए नियुक्त कोई भी अधिकारी, मालिक को लिखित रूप में नोटिस देकर निर्देशित कर सकता है।

(2) निर्देशों की प्रतियां केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या अधिकारियों द्वारा मांग पर प्रदान की जाएंगी।

(3) प्रत्येक उत्पादन स्टेशन, संलग्न सबस्टेशन, संलग्न स्विच-स्टेशन और प्रत्येक कारखाने या अन्य परिसर का मालिक, जिस पर यह नियम लागू होता है, यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित सभी अधिकृत व्यक्ति परिचित हैं और उप-में निर्दिष्ट निर्देशों को लागू करने में सक्षम हैं। नियम (मैं).

(4) हर तरह से उच्च वोल्टेज या अतिरिक्त-उच्च वोल्टेज उत्पादन स्टेशन, उप-स्टेशन या स्विच स्टेशन पर एक कृत्रिम श्वासयंत्र उपलब्ध कराया जाएगा और उसे अच्छी कार्यशील स्थिति में रखा जाएगा।

(45) उपभोक्ताओं, [मालिकों, अधिभोगियों], विद्युत, ठेकेदारों, विद्युत कर्मियों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली सावधानियां- (1) मौजूदा में परिवर्धन, परिवर्तन, मरम्मत और समायोजन सहित कोई विद्युत स्थापना कार्य नहीलैंप, पंखे, फ़्यूज़, स्विच, कम वोल्टेज वाले घरेलू उपकरणों और फिटिंग के ऐसे प्रतिस्थापन को छोड़कर, जो किसी भी तरह से इसकी क्षमता या चरित्र को नहीं बदलता है, किसी भी [उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, मालिक या की ओर से परिसर में किया जाएगा। अधिभोगी] ऐसे [उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, मालिक या अधिभोगी] को आपूर्ति के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार को छोड़कर और सक्षमता का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति की प्रत्यक्ष देखरेख में और एक धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी या मान्यता प्राप्त परमिट:

बशर्ते कि केंद्र सरकार के लिए या उसकी ओर से निष्पादित कार्यों के मामले में और खानों, तेल क्षेत्रों और रेलवे में स्थापना के मामले में, केंद्र सरकार और अन्य मामलों में राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा छूट दे सकती है। , ऐसी शर्तों पर जो यह लागू कर सकता है, इसमें वर्णित

कोई भी ऐसा कार्य या तो आम तौर पर या इस उप-नियम के किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में इस उप-नियम से इतना अधिक है कि इस तरह के काम को पूरा करने की आवश्यकता होती है इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त विद्युत अनुबंध द्वारा

(2) उप-नियम (1) के उल्लंघन में किया गया कोई भी विद्युत स्थापना कार्य या तो ऊर्जावान नहीं होगा या किसी आपूर्तिकर्ता के कार्यों से जुड़ा नहीं होगा।]

(46) स्थापना का आवधिक निरीक्षण और परीक्षण, - (I)(ए) जहां एक स्थापना पहले से ही आपूर्तिकर्ता की आपूर्ति प्रणाली से जुड़ी हुई है, ऐसे प्रत्येक स्थापना का समय-समय पर निरीक्षक (या किसी अन्य) द्वारा पांच साल से अधिक के अंतराल पर निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा। निरीक्षक की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी) या आपूर्तिकर्ता द्वारा जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जा सकता है या (केंद्र सरकार से संबंधित या उसके नियंत्रण में स्थापना के मामले में, और खानों में स्थापना के मामले में, केंद्र सरकार द्वारा तेल क्षेत्र और रेलवे।

(एए) आपूर्तिकर्ता से संबंधित उच्च वोल्टेज और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों का आवधिक निरीक्षण और परीक्षण भी निरीक्षक या निरीक्षक की सहायता के लिए नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पांच वर्ष से अधिक के अंतराल पर नहीं किया जाएगा।

(b) जहां आपूर्तिकर्ता को केंद्र या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा इंस्टॉलेशन का निरीक्षण और परीक्षण करने का निर्देश दिया जाता है, तो वह इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित फॉर्म में संबंधित उपभोक्ता को इंस्टॉलेशन की स्थिति के बारे में रिपोर्ट करेगा और इसकी एक प्रति जमा करेगा। ऐसी रिपोर्ट इंस्पेक्टर को या इंस्पेक्टर की सहायता के लिए नियुक्त और नियम 4 ए के उप-नियम (2) के तहत अधिकृत किसी अधिकारी को।

(c) निरीक्षक के अनुमोदन के अधीन, अनुलग्नक IX A में निहित निरीक्षण रिपोर्ट के प्रपत्र, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक भिन्नताओं के साथ, इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।

(2)(ए) ऐसे निरीक्षण और परीक्षण के लिए शुल्क प्रत्येक वर्ग के उपभोक्ताओं के मामले में, जैसा भी मामला हो, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और उपभोक्ता द्वारा अग्रिम रूप से भुगतान किया जाएगा।

(b) यदि कोई उपभोक्ता शुल्क-नोटिस में निर्दिष्ट तिथि पर या उससे पहले शुल्क का भुगतान करने में

विफल रहता है, तो ऐसे उपभोक्ता की स्थापना के लिए आपूर्ति निरीक्षक के निर्देश के तहत काट दी जाएगी, हालांकि, ऐसा वियोग होगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसा करने के इरादे के बारे में उपभोक्ता को लिखित में सात दिन का नोटिस दिए बिना ऐसा नहीं किया जाएगा।

(c) किसी भी इंस्टालेशन के मालिक द्वारा इंस्पेक्टर या उसकी सहायता के लिए नियुक्त और नियम 4 ए के उप-नियम (2) के तहत निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा बताए गए अपने इंस्टालेशन में दोषों को ठीक करने में असफल होने की स्थिति में अनुबंध IX और उसमें दर्शाई गई सीमा के भीतर, ऐसे इंस्टॉलेशन को निरीक्षक के निर्देशों के तहत/ऐसे इंस्टॉलेशन के मालिक को नोटिस के साथ जब्त करने के बाद डिस्कनेक्ट किया जा सकता है:

बशर्ते कि नियम 6 के तहत अपील किए जाने की स्थिति में इंस्टॉलेशन को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा और अपीलीय प्राधिकारी ने कनेक्शन काटने के आदेश पर रोक लगा दी है:

बशर्ते कि नोटिस में दर्शाया गया समय किसी भी स्थिति में 48 घंटे से कम नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि इस खंड में निहित किसी भी बात का नियम 49 के लागू होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) इस नियम के प्रावधानों के बावजूद, उपभोक्ता हर समय खतरे से मुक्त स्थिति में अपने इंस्टॉलेशन के रखरखाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। (जोर देने के लिए रेखांकित)

(21) **रिट क्षेत्राधिकार में मुआवज़ा देने के लिए कानून की स्थिति पर, श्री मल्होत्रा ने इस न्यायालय में अपने लिखित प्रस्तुतीकरण में निम्नलिखित कहा है: -**

"2. रिट क्षेत्राधिकार में मुआवजा देने के लिए कानून की स्थिति को नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है। और डॉ. महमूद नैयरआजम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक हैं, उनके पास न केवल शक्ति और अधिकार क्षेत्र है, बल्कि राहत देने का दायित्व भी है। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग। इस प्रकार मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए रिट क्षेत्राधिकार में मुआवजे का पुरस्कार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है।

3. सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जहां संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पीड़ितों के मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया जाता है, राज्य को नागरिक के अधिकार के बावजूद, उसके

अधिकारियों द्वारा पीड़ित व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए बुलाया जा सकता है। सिविल मुकदमे या आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से उपचार के लिए। इस तरह,संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए पीड़ित पक्ष को मुआवजा देकर और गलत करने वाले को दंडित करके और सार्वजनिक गलती के लिए राज्य पर दायित्व तय करके मौद्रिक राहत प्रदान की जा सकती है, जो अपने सार्वजनिक कर्तव्य में विफल रहा है। नागरिक/पीड़ित व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।

4. इस प्रकार, कानून के उपरोक्त सिद्धांत का पालन करते हुए, यह माननीय न्यायालय गलत काम करने वाले को दंडित करने और अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने वाले उत्तरदाताओं पर सार्वजनिक गलती के लिए दायित्व तय करने के माध्यम से रिट क्षेत्राधिकार में राहत को ढालकर मुआवजा दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के विचार में, मुआवजे का भुगतान क्षति के लिए एक नागरिक कार्रवाई के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए किए गए गलत कार्यों के लिए सार्वजनिक कानून के तहत "मौद्रिक संशोधन" करना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, यह पीड़ित पक्ष के अधिकार से स्वतंत्र है कि वह निजी कानून के तहत सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत में शुरू किए गए मुकदमे के माध्यम से अपकृत्य के आधार पर मुआवजे का दावा कर सके या/और अपराधी पर मुकदमा चला सके। दंड विधान के अंतर्गत. इस प्रकार, "अनुकरणीय क्षति" का यह दावा कानून की उपरोक्त निर्धारित स्थिति के तहत इस माननीय न्यायालय के समक्ष विचारणीय है और पीड़ित को मौद्रिक मुआवजा दिया जा सकता है।

(22) **विशेष रूप से बिजली के मामलों में मुआवज़ा देने के लिए कानून की स्थिति पर, श्री मल्होत्रा के शोध के परिणामस्वरूप निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ और केस कानून का समर्थन प्राप्त हुआ हैः -**

"6. राज्य विद्युत बोर्डों की ओर से वैधानिक कर्तव्यों/दायित्वों के उल्लंघन के लिए मुआवजा देने में "सख्त दायित्व" और परिणामी लापरवाही के सिद्धांत को बरकरार रखते हुए, शीर्ष न्यायालय और मद्रास, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल और गुजरात के उच्च न्यायालयों ने फैसला सुनाया है। रिट/अपील क्षेत्राधिकार में पीड़ितों को मुआवजा यह मानते हुए कि बिजली अधिकारी भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (पहले भारतीय विद्युत अधिनियम 1910, विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों) के प्रावधानों के तहत सावधानियों/सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।)। नाकबलियतलापरवाही के समान ऐसे वैधानिक कार्यों/कर्तव्यों को बिजली उपभोक्ता के कथित वैधानिक दायित्वों से दूर नहीं किया जा सकता है। लाइव तारों द्वारा बिजली के झटके के लिए "सख्त दायित्व" की आवश्यकता होती है और यह लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाले दायित्व से भिन्न होता है और "सख्त

दायित्व" के मामलों में प्रासंगिक नहीं है। इस प्रकार, बिजली अधिकारी इस बात के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या उपभोक्ता द्वारा सावधानी बरतने से नुकसान से बचा जा सकता था। ऊपर उद्धृत वैधानिक अधिनियमों के तहत बिजली के झटके से उत्पन्न दुर्घटनाओं और देयता के कारण होने वाली चोटों/जीवन की हानि के लिए मुआवजा देने वाले निम्नलिखित निर्णय, कानून के उपरोक्त निर्धारित सिद्धांतों के समर्थन में यहां उद्धृत किए गए हैं:

a. ***मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड*** **बनाम शैल कुमारी**

b. ***एन.निज़ालकोडी बनाम अध्यक्ष टीएनईबी./डब्ल्यूपी (एमडी) संख्या 6634 ऑफ़ 2007 का फैसला 16.08.2012-एसबी मद्रास उच्च न्यायालय का***

c. ***ए.सुब्रमणि बनाम तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, डब्ल्यूपी (एमडी) संख्या 14011 ऑफ़ 2010 का निर्णय 23.02.2012 को - मद्रास उच्च न्यायालय का एसबी***

d. ***रमेश सिंह पवार*** **बनाम एमआर बिजली बोर्ड और अन्य**।

e. ***ए. कृष्णा पात्रा*** **बनाम उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड**।

f. **केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम सुरेश कुमार**

g. **पटेल मगनभाई बापूजीभाई बनाम पटेल ईश्वरभाई मोतीभाई**।

"पूर्वोक्त स्थिति में, कानून की स्थापित स्थिति इंगित करती है कि सख्त दायित्व का नियम और संभावित जोखिम का सिद्धांत बिजली अधिकारियों को पीड़ित को मुआवजा देने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी बनाता है। जब तक तारों के माध्यम से प्रसारित बिजली का वोल्टेज संभावित रूप से खतरनाक आयामों का होता है, तब तक इसकी आपूर्ति के प्रबंधकों का अतिरिक्त कर्तव्य होता है कि वे ऐसी ऊर्जा को बाहर निकलने से रोकने के लिए सभी सुरक्षा उपाय करें जो बिजली के झटके का कारण बनती हैं। इस प्रकार, सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करना बिजली अधिकारियों का वैधानिक दायित्व, कर्तव्य और जिम्मेदारी है और ऐसा करने में विफलता के कारण सुरक्षा उपायों की कमी के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए मुआवजा देना पड़ता है।

(23) **वर्तमान मामले में कानून की स्थापित स्थिति की प्रयोज्यता पर, श्री मल्होत्रा को निम्नलिखित कहना है: -**

"8. याचिका में दिए गए कथनों को पढ़ने से पता चलता है कि नाबालिग बच्चे रमन को 03.11.2011 को उसके घर की खुली छत पर ओवरहेड लाइन/तार से करंट लग गया था, जो प्रतिवादी संख्या द्वारा प्रदान

किया गया था। 1 से 4 तक याचिकाकर्ता के घर की छत पर एक एंगल आयरन स्थापित करके, एक लाइव ओवरहेड लाइन/तार के माध्यम से याचिकाकर्ता के आवासीय परिसर में विद्युत ऊर्जा प्रदान करने की यह विधि और विधि इसके विपरीत एक एंगल आयरन स्थापित करके। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के प्रावधान स्पष्ट रूप से इसके घोर उल्लंघन को स्थापित करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सावधानी, सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपाय या अन्य कदम नहीं उठाए गए कि लाइव ओवरहेड लाइन/तार मानव संपर्क से बचने के लिए उचित और पर्याप्त दूरी पर थे। इसलिए, लाइव ओवरहेड लाइन/तार को स्थापित करने और इसे खुला रखने से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि उच्च वोल्टेज विद्युत ऊर्जा संचारित करने वाले तार के संपर्क से दुर्घटना से बचने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया था। इस मामले में 4 साल के नाबालिग बच्चे को सौ प्रतिशत स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा है।

9. उपरोक्त स्थिति में, ऊपर उद्धृत निर्णयों में सिद्धांतों को लागू करना और सख्त दायित्व के सिद्धांत पर वर्तमान मामले में पूरी तरह से आकर्षित होना और कोई सुरक्षा उपाय, जांच, संतुलन प्रदान न करने में उत्तरदाताओं की लापरवाही को ध्यान में रखना याचिकाकर्ता को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देना उत्तरदाताओं पर एक स्पष्ट वैधानिक दायित्व है। इसके अलावा, उत्तरदाताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आवधिक जांच करने में सावधानी और सावधानी नहीं बरती कि एंगल आयरन के माध्यम से स्थापित लाइव तार का पता लगाया जाना चाहिए और तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। विद्युत ऊर्जा के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में, उत्तरदाता लाइव ओवरहेड लाइन/तार को हटाना सुनिश्चित नहीं करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं जो एक संभावित खतरनाक और अस्थिर जोखिम वाली स्थिति थी। इसलिए, लापरवाही के कारण भी, उत्तरदाता मुआवजे के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

(24) मेरा मानना है कि स्वाभाविक रूप से खतरनाक चीज, जो कि प्राकृतिक रूप से बिजली है, को भागने से रोकने के लिए सभी उचित साधनों का उपयोग करने में विफलता पर, देखभाल का मानक बहुत ऊंचा होगा और आपूर्तिकर्ता पर यह दिखाने की जिम्मेदारी होगी कि कोई लापरवाही नहीं हुई है। इस मामले में, प्रतिवादी-निगम ने इस न्यायालय की संतुष्टि के लिए जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं किया है।

(25) हालांकि नीलाबती बचेरा (सुप्रा) ने हिरासत में मौत के मामले को निपटाया, लेकिन "सख्त दायित्व" के आधार पर जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामलों में मुआवजे के पुरस्कार के सिद्धांत अन्य तथ्य स्थितियों में सार्वभौमिक अनुप्रयोग के हैं। हस्तक्षेप। ऐसे मामलों में जहां इस तरह का कोई तथ्यात्मक विवाद है जिसे रिट क्षेत्राधिकार में संबोधित नहीं किया जा सकता है, तो क्या याचिकाकर्ता को सिविल मुकदमे के सामान्य उपाय में डाल दिया जाना चाहिए यदि उसका मुआवजे का दावा वास्तव में प्रकृति में विवादास्पद है जिसके लिए ऐसे अधिकारों को स्थापित करने के लिए साक्ष्य स्वीकार करने की आवश्यकता है। रिट कार्यवाही में सुधार योग्य "सख्त दायित्व" पर आधारित

अधिकारों के बीच अंतर जहां सार्वजनिक कानून तत्व शामिल है और कपटपूर्ण दायित्व को ध्यान में रखना होगा। संप्रभु प्रतिरक्षा "सख्त दायित्व" पर लागू नहीं होती है और इसका उपयोग अपकृत्य पर आधारित कार्रवाई में निजी कानून में बचाव के रूप में किया जा सकता है। नीलाबती बेहरा के पैराग्राफ 10 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार कहा: -

> *"10. रुदुल साह बनाम बिहार राज्य और अन्य, [1983] 3 एससीआर 508, सेबेस्टियन एम. होंग रे बनाम भारत संघ और अन्य, [1984] 1 एससीआर 904 और [1984] 3 में इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए एससीआर 544, भीम सिंह बनाम स्टेल ऑफ जेएंडके [1984] सप्लिमेंट। एस.सी.सी. 504 और [1985] 4 एस.सीसी. 677, सहेली, एक महिला संसाधन केंद्र और अन्य बनाम आयुक्त* पुलिस, दिल्ली पुलिस मुख्यालय और अन्य, /1990] 1 एससीसी 422 और महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम रविकांत एस.पाटिल, [1991] 2 एससीसी 373, वर्तमान मामले में मुआवजा देने के लिए उड़ीसा राज्य का दायित्व संदेह नहीं किया जा सकता है और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा इस पर उचित रूप से विवाद नहीं किया गया है। हालाँकि, उस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से बताना उचित होगा जिसके आधार पर ऐसे मामलों में मुआवजे के भुगतान के लिए राज्य का दायित्व उत्पन्न होता है और इस दायित्व और निजी कानून में अपकार की कार्रवाई में मुआवजे के भुगतान के दायित्व के बीच अंतर होता है। . इसका सीधा उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजे का पुरस्कार सार्वजनिक कानून में उपलब्ध एक उपाय है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सख्त दायित्व पर आधारित है। संप्रभु प्रतिरक्षा लागू नहीं होती है, भले ही यह अपकृत्य पर आधारित कार्रवाई में निजी कानून में बचाव के रूप में उपलब्ध हो सकती है। यह ध्यान में रखने योग्य दो उपायों के बीच का अंतर है जो उस आधार को भी इंगित करता है जिसके आधार पर ऐसी कार्यवाही में मुआवजा दिया जाता है। अब हम इस सिद्धांत पर आगे की चर्चा से पहले इस न्यायालय के पहले के निर्णयों के साथ-साथ कुछ अन्य निर्णयों का भी उल्लेख करेंगे।"

(26) रिपोर्ट के पैराग्राफ 17, 18, 19 और 22 में न्यायालयों के पालन और लागू करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:-

> *"17. यह इस प्रकार है कि मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए 'सार्वजनिक कानून में मुआवजे के लिए दावा', जिसकी सुरक्षा की गारंटी संविधान में दी गई है, ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए एक स्वीकृत उपाय है, और ऐसा दावा मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक उपाय का सहारा लेकर बनाए गए सख्त दायित्व के आधार पर 'मौलिक*

अधिकार के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के लिए निजी कानून में उपाय से अलग और इसके अतिरिक्त' है। संप्रभु प्रतिरक्षा की रक्षा अनुपयुक्त है, और मौलिक अधिकारों की गारंटी की अवधारणा से अलग है, संवैधानिक उपचार में ऐसी रक्षा उपलब्ध होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। यह वह सिद्धांत है जो गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजे के पुरस्कार को उचित ठहराता है संविधान द्वारा, जब राज्य या उसके सेवकों द्वारा अपनी शक्तियों के कथित अभ्यास में किए गए उल्लंघन के लिए निवारण का यही एकमात्र व्यावहारिक तरीका उपलब्ध है, और मौलिक अधिकार के प्रवर्तन का दावा इसके तहत सार्वजनिक कानून में उपाय का सहारा लेकर किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 का सहारा लेकर संविधान। रुदुल साह में यही संकेत दिया गया था और यह बाद के निर्णयों का आधार है जिसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मुआवजा दिया गया था।

18. इस विषय पर एक उपयोगी चर्चा जो मुआवजे के पुरस्कार को सक्षम करने वाले मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सख्त दायित्व के आधार पर सार्वजनिक कानून में उपचार के बीच अंतर को सामने लाती है, जिसके लिए संप्रभु प्रतिरक्षा की रक्षा अनुपयुक्त है, और निजी कानून उपाय, जिसमें प्रतिवर्ती है अपकृत्य में राज्य का उत्तरदायित्व उत्पन्न हो सकता है, यह रतनलाल और धीरजलाल के लॉ ऑफ़ टॉर्ट्स, 22वें संस्करण, 1992 में न्यायमूर्ति जीपी सिंह द्वारा पृष्ठ 44 से 48 पर पाया जा सकता है।

*19. इस दृष्टिकोण को भागलपुर अंधाधुंध मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों से समर्थन मिलता है: खर्ती और अन्य (द्वितीय) बनाम बिहार राज्य और अन्य, [1981/1 एससीसी 627 और खर्ती और अन्य (टीवी) बनाम बिहार राज्य और अन्य। [1981 जे 2 एससीसी 493, जिसमें यह कहा गया था कि अदालत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के मामले में राहत देने में असहाय नहीं है, और उसे इस उद्देश्य के लिए नए उपकरण बनाने और नए उपचार तैयार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन बहुमूल्य मौलिक अधिकारों की पुष्टि करते हुए। यह भी संकेत दिया गया कि राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक तथ्यों का पता लगाने के लिए आवश्यक जांच करने के लिए मामले के तथ्यों के अनुरूप उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।*गारंटीशुदा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निवारण का उपलब्ध तरीका। हाल ही में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में। [जे991] 4 एससीसी 584, मिश्रा, सीजे। कहा गया है कि 'हमें अपना स्वयं का कानून विकसित करना होगा और यदि हम पाते हैं कि जो असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई है और जो भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना है, उससे निपटने के लिए

दायित्व का एक नया सिद्धांत बनाना आवश्यक है, तो कोई कारण नहीं है कि हमें संकोच करना चाहिए दायित्व के ऐसे सिद्धांत को विकसित करना *" उसी प्रभाव की टिप्पणियाँ हैं वेंकटचलैया, जे. (जैसा कि वह तब थे), जिन्होंने राहत देने की अदालत की शक्ति के संबंध में भोपाल गैस मामले में अग्रणी निर्णय दिया था*

XXX XXXXXX XXX

22. उपरोक्त चर्चा उन सिद्धांतों को इंगित करती है जिन पर संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायालय की शक्ति का प्रयोग मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजा देने के लिए किया जाता है। यह रुदुल साह में इंगित किया गया था और उसमें पहले की गई कुछ अन्य टिप्पणियाँ, जो उसमें बताए गए सिद्धांत के प्रभाव को कम कर सकती हैं, वास्तव में उस सिद्धांत से अलग नहीं होती हैं। रुदुल साह और उस पंक्ति के अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसलों को इसी तरह समझा जाना चाहिए और कस्तूरी लाल को उससे अलग किया जाना चाहिए। हमने इस तरह की कार्यवाहियों में मुआवज़ा देने के औचित्य के बारे में उठाए गए संदेह को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर कुछ विस्तार से विचार किया है, बजाय इसके कि दावेदार को अपकृत्य की कार्रवाई का सहारा लेकर क्षति की वसूली की सामान्य प्रक्रिया का सहारा लिया जाए। . वर्तमान मामले में, निष्कर्ष पर पहुंचने पर, यह याचिकाकर्ता को उसके बेटे की हिरासत में मौत के लिए मुआवजा देने का एक स्पष्ट मामला है। " (जोर देने के लिए रेखांकित)

(27) डॉ. महमूद नैय्यर आजम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रश्न पर विचार करते हुएपुलिस हिरासत में यातना और उत्पीड़न के एक मामले में मुआवजा, यह देखा गया कि जब मामला सार्वजनिक कानून उपचार का है, तो मुआवजे की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि यह निजी कानून के तहत पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध एक स्वतंत्र अधिकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंतर्संबंध सार्वजनिक कानून उपचार के माध्यम से निर्णयित निजी कानून की चोटों के बीच है।

(28) ***मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड* बनाम शैल कुमारी और अन्य** *में* तथ्यात्मक स्थिति यह थी कि एक बिजली का तार टूट गया था और सार्वजनिक सड़क पर बारिश के पानी से आंशिक रूप से डूबा हुआ था, जब मृतक अनजाने में साइकिल पर सवार होकर तार पर चढ़ गया, जिससे तार मुड़ गया और तुरंत उसकी जान चली गई। न्यायालय ने कहा:-

1. . यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विशेष इलाके में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी वैधानिक रूप से बोर्ड को सौंपी गई थी। यदि इस प्रकार प्रसारित ऊर्जा किसी इंसान को चोट पहुंचाती है या उसकी मृत्यु का कारण बनती है, जो अनजाने में इसमें फंस जाता है तो पीड़ित को मुआवजा

देने का प्राथमिक दायित्व विद्युत ऊर्जा के आपूर्तिकर्ता का है। जब तक तारों के माध्यम से प्रसारित बिजली का वोल्टेज संभावित रूप से खतरनाक आयाम का है, तब तक इसकी आपूर्ति के प्रबंधकों का अतिरिक्त कर्तव्य है कि वे ऐसी ऊर्जा को बाहर निकलने से रोकने के लिए सभी सुरक्षा उपाय करें या यह देखें कि टूटा हुआ तार सड़क पर नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसी सड़क का उपयोग करने वाले जोखिम में होंगे। बोर्ड के प्रबंधन की ओर से यह कोई बचाव नहीं है कि किसी ने अपनी निजी संपत्ति में ऐसी ऊर्जा प्रवाहित करके शरारत की है और बिजली का झटका ऐसी डायवर्टेड लाइन से हुआ था। आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधकों का ध्यान आवश्यक उपकरणों को स्थापित करके ऐसी चोरी को रोकने का है। किसी भी दर पर, यदि कोई विद्युत प्रवाहित तार टूट कर सार्वजनिक सड़क पर गिर जाता है तो उस पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बाधित हो जाना चाहिए। ऐसी खतरनाक वस्तुओं की देखरेख करने वाले अधिकारियों का अतिरिक्त कर्तव्य है कि वे ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करें।

8. यहां तक कि यह मानते हुए कि ऐसे सभी उपाय अपनाए गए हैं, एक व्यक्ति जो मानव जीवन के लिए खतरनाक या जोखिम भरा कार्य करता है, किसी अन्य व्यक्ति को लगी चोट की भरपाई के लिए अपकृत्य कानून के तहत उत्तरदायी है, भले ही उसकी ओर से कोई भी लापरवाही या असावधानी क्यों न हो। ऐसे उपक्रमों के प्रबंधकों की. ऐसी देनदारी का आधार ऐसी गतिविधि की प्रकृति में निहित अनुमानित जोखिम है। ऐसे व्यक्ति पर डाले गए दायित्व को, कानून में, "सख्त दायित्व" के रूप में जाना जाता है। यह उस दायित्व से भिन्न है जो इस तरह से लापरवाही या गलती के कारण उत्पन्न होता है यानी लापरवाही की अवधारणा यह समझती है कि उचित सावधानी बरतकर संभावित नुकसान से बचा जा सकता है। यदि प्रतिवादी ने वह सब किया जो नुकसान से बचने के लिए किया जा सकता था तो उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब कार्रवाई किसी लापरवाही पर आधारित हो। लेकिन इस तरह का विचार सख्त दायित्व के मामलों में प्रासंगिक नहीं है जहां प्रतिवादी को इस बात के बावजूद उत्तरदायी ठहराया जाता है कि क्या वह सावधानी बरतकर विशेष नुकसान से बच सकता था।

9. सख्त दायित्व के सिद्धांत की उत्पत्ति अंग्रेजी कॉमन लॉ में हुई जब इसे रायलैंड्स के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया गया था वी. फ्लेचर (1868 कानून रिपोर्ट (3) एचएल 330)। उक्त नियम के लेखक ब्लैकबर्न जे. ने उक्त निर्णय में इस प्रकार कहा था:

> *''क़ानून का नियम यह है कि जो व्यक्ति, अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए, अपनी भूमि पर लाता है और वहां कुछ भी इकट्ठा करता है और रखता है जिससे शरारत होने की संभावना हो, यदि वह बच जाता है, तो उसे इसे अपने जोखिम पर रखना होगा; और यदि वह ऐसा करता है तो*

प्रथम दृष्टया वह उस सभी क्षति के लिए उत्तरदायी है जो इसके भागने का स्वाभाविक परिणाम है।"

10. सख्त दायित्व के सिद्धांत के लिए केस कानून के माध्यम से सात अपवाद तैयार किए गए हैं। इनमें से एक अपवाद को छोड़कर अन्य अपवादों की गणना करना अनावश्यक है। "अजनबी का कार्य अर्थात यदि पलायन किसी अजनबी के अप्रत्याशित कार्य के कारण हुआ, तो नियम लागू नहीं होता", (टोर्ट पर रेज 535 विनफील्ड, 15 वां संस्करण देखें।)

*11. सख्त दायित्व के नियम को इंग्लैंड में बाद के कई निर्णयों में अनुमोदित और पालन किया गया है। हाल ही में*उक्त सिद्धांत को मान्यता देने का निर्णय कैम्ब्रिज वाटर कंपनी लिमिटेड बनाम ईस्टर्न काउंटिज़ लेदर पीएलसी मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा दिया गया है। {1994(1) ऑल इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट्स (एचएल) 53)। उक्त सिद्धांत को भारत में स्वीकृति मिली, और उच्च न्यायालयों के निर्णय उस प्रभाव के एक उदाहरण हैं। चरण लाल साहू बनाम भारत संघ में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ और गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम रमन भाई प्रभात भाई में एक डिवीजन बेंच ने रायलैंड्स बनाम प्लेचर में सिद्धांत का अनुमोदन किया था। उपरोक्त दो निर्णयों का हवाला देकर इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कौशनुमा बेगम बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2001) 2 एससीसी 9} में उसी सिद्धांत को दोहराया है।

12. <u>एमसी मेहता बनाम भारत संघ में</u>यह न्यायालय यह कहते हुए सख्त दायित्व के नियम से भी आगे निकल गया है कि "जहां कोई उद्यम खतरनाक या स्वाभाविक रूप से खतरनाक गतिविधि में लगा हुआ है और ऐसी गतिविधि के संचालन में दुर्घटना के कारण किसी को नुकसान होता है, तो उद्यम सख्ती से और दुर्घटना से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है; ऐसा दायित्व रायलैंड्स बनाम प्लेचर के नियम के तहत सख्त दायित्व के सिद्धांत के किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है। (जोर देने के लिए रेखांकित)

(29) उपरोक्त मामले में बिजली के आपूर्तिकर्ता का बचाव यह था कि बिजली के झटके से हुई मौत आपूर्ति लाइन से अनधिकृत रूप से बिजली ऊर्जा निकालने के लिए एक अजनबी द्वारा की गई गुप्त चोरी के कारण हुई थी और इसलिए गलती करने वाले पर ही इसका भार डाला जाना चाहिए। नुकसान. सर्वोच्च न्यायालय ने इस बचाव को स्वीकार नहीं किया और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे को बरकरार रखा।

(30) **ए कृष्णा पात्रा में***(सुप्रा),*बिजली के झटके से मौत के एक मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की: -

*"8. ट्रांसमिशन लाइन के टूटने या इसी तरह के कारण के कारण बिजली के झटके से मौत के मामले में उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड के दायित्व से संबंधित प्रश्न, हाल के दो मामलों में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया, अर्थात् श्रीमती। रजनी देवी बनाम अध्यक्ष, उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड, (1996) 8 जे कट एलटी 353, और उत्तम साहू वाई। अध्यक्ष, उड़ीसा. राज्य विद्युत बोर्ड, ('1996) 2 ओएलआर 99। इन दोनों मामलों में, मौत का कारण टूटी हुई लाइन के संपर्क में आने के कारण करंट लगना था, जो चार्ज रहती थी। रजनी देवी के मामले (सुप्रा) में प्रश्न से निपटने के दौरान, भारतीय विद्युत नियमों के नियम 91 का उल्लेख करने के बाद, जो सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरणों से संबंधित है और इंग्लैंड के हेल्सबरी कानून, चौथे संस्करण के खंड 37 में शामिल पैराग्राफ 35 और 36, यह माना गया है कि कानून स्पष्ट है कि ओएसईबी को ओवर-हेड लाइनों के माध्यम से ऊर्जा के संचरण से जुड़े कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उसमें यह भी संकेत दिया गया था कि ऐसे मामलों में, बोर्ड पर यह स्थापित करने का बोझ भारी होगा कि वे विद्युत प्रवाह को भागने से रोक सकते थे क्योंकि ऐसी चीजें नहीं होती हैं, यदि जिनके पास प्रबंधन है वे उचित देखभाल करते हैं। मौजूदा मामले में, यह ओएसईबी की दलील है कि न तो उन्होंने लापरवाही की थी और न ही पर्यवेक्षण की कमी के कारण लाइव कंडक्टर को तोड़ा गया था, हालांकि, यह इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की रिपोर्ट से गलत है जो इंगित करता है कि इनमें से एक चरणबद्ध कंडक्टर टूट गए क्योंकि उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई थी और वे यांत्रिक रूप से कमजोर हो गए थे। यह स्पष्ट रूप से विरोधी पक्षों की ओर से देखभाल, सावधानी और उचित पर्यवेक्षण की कमी को इंगित करता है। नहीं, यह वस्तु उदासीनता के एक स्पष्ट मामले को इंगित करता है, क्योंकि यह देखना विपरीत पक्षों का अनिवार्य कर्तव्य था कि एक यांत्रिक रूप से अस्वस्थ और कमजोर कंडक्टर को बदल दिया जाए, जो कि बहुत गंभीर परिणामों को देखते हुए होने की संभावना है, जो वास्तव में हुआ है इस मामले में। ऐसे कंडक्टरों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा के संचरण की अनुमति देना जो अपनी उपयोगिता समाप्त कर चुके हैं और यांत्रिक रूप से कमजोर और अस्वस्थ हो गए हैं, लापरवाही का एक संकेत होगा। यदि ऐसा कोई कंडक्टर टूट जाता है और लाइन विद्युत रूप से हानिरहित नहीं हो जाती है और परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यह अपने आप में ओएसईबी पर लापरवाही का आरोप लगाने का एक आधार होगा।*मामले में, हमारा मानना है कि समझाने का बोझ ओएसईबी पर होगा, न कि दावेदार पर ओएसईबी की लापरवाही स्थापित करने का, याचिकाकर्ता को और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है।

9. किसी अपरिहार्य दुर्घटना या दैवीय कृत्य की दलील, सुनवाई के चरण में सामने आने पर, विरोधी पक्षों की सहायता के लिए नहीं आ सकती। अपरिहार्य दुर्घटना या दैवीय कृत्य के प्रश्न पर विचार

करते समय, न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा लिखित लॉ ऑफ टॉर्ट्स, 22वें संस्करण के एक अंश को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा, जो इस प्रकार है:

> *अपरिहार्य दुर्घटनाओं के सभी कारणों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: (1) वे जो प्रकृति की प्राथमिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं जो मनुष्य की एजेंसी या अन्य कारण से असंबद्ध होते हैं; और (2) जिनकी उत्पत्ति या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से मनुष्य की एजेंसी में है, चाहे कमीशन या चूक, गैर-व्यवहार या दुर्व्यवहार के कार्यों में, या प्राकृतिक शक्तियों की एजेंसी से स्वतंत्र किसी अन्य कारण से। ईश्वर का कार्य शब्द पूर्व वर्ग पर लागू होता है। "*

<u>अपरिहार्य दुर्घटना एक ऐसी घटना है जो न केवल मनुष्य की इच्छा की सहमति के बिना घटती है, बल्कि उसे रोकने के उसके सभी प्रयासों के बावजूद भी घटती है। इसका मतलब है, एक दुर्घटना जो शारीरिक रूप से अपरिहार्य है जिसे मानवीय कौशल या दूरदर्शिता से रोका नहीं जा सकता है।</u>हम पहले ही विद्युत निरीक्षक की रिपोर्ट का उल्लेख कर चुके हैं जो इंगित करती है कि कंडक्टर टूट गए क्योंकि उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई थी और वे यांत्रिक रूप से कमजोर और अस्वस्थ हो गए थे। यदि बोर्ड ने उचित देखभाल और पर्यवेक्षण किया होता, तो वह समय रहते यांत्रिक रूप से अस्वस्थ और कमजोर कंडक्टर को बदलने के लिए उचित और त्वरित कदम उठा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि ओएसईबी सामान्य देखभाल, सावधानी और उचित पर्यवेक्षण के जरिए घटना को रोक नहीं सका। इस प्रकार, यह ऐसा मामला नहीं है जहां ओएसईबी की ओर से इसे रोकने के सभी प्रयासों के बावजूद दुर्घटना हुई हो। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि दुर्घटना पूरी तरह से ओएसईबी और उसके पदाधिकारियों की ओर से देखभाल और सावधानी की कमी के कारण हुई थी।

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकलता है कि अपरिहार्य दुर्घटना की दलील पूरी तरह से गलत है अपने दायित्व से बाहर निकलने के लिए विरोधी पक्षों की सहायता नहीं कर सकता।

10. 'ईश्वर का कार्य' मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना एक अपरिहार्य या अपरिहार्य दुर्घटना है; कुछ ऐसी दुर्घटनाएँ जिन्हें मानवीय दूरदर्शिता नहीं समझ सकी और जिसके परिणाम से कोई मानवीय सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां यह घटना मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त प्राकृतिक शक्तियों के अप्रत्याशित संचालन के कारण हुई थी, जिसके घटित होने का अनुमान लगाने या इसे रोकने के लिए किसी भी उचित मानवीय दूरदर्शिता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। इसके विपरीत, रिकॉर्ड पर सामग्री स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि लेकिन उदासीनता और निष्क्रियता के लिए - यांत्रिक रूप से खराब और कमजोर कंडक्टर को बदलने में ओएसईबी की लापरवाही, जिसने अपनी उपयोगिता समाप्त

कर दी थी, घटना नहीं हुई होगी।

11. इस प्रकार, हालांकि विद्युत अधिनियम 1910 और विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के तहत, विद्युत ऊर्जा का संचरण ओएसईबी को विद्युत ऊर्जा के पलायन के लिए उपद्रव के दायित्व से मुक्त कर सकता है, लेकिन लापरवाही के मामले में या; हम कह सकते हैं, देखभाल की कमी के कारण, चूँकि OSEB ऐसे पलायन को रोकने के लिए सभी उचित साधनों का उपयोग करने में विफल रहता है, OSEB उत्तरदायी होगा, क्योंकि बिजली की स्वाभाविक रूप से खतरनाक प्रकृति को देखते हुए, देखभाल का मानक आवश्यक रूप से बहुत होगा उच्च और यह ओएसईबी के लिए होगा कि वह दिखाए कि मौजूदा मामले में कोई लापरवाही नहीं हुई थी.

*12. जैसा कि रायलैंड्स बनाम फ्लेचर (186 एस- एलआर 3 एचएल 330) (सुप्रा) के मामले का संदर्भ दिया गया था, उसी पर संक्षेप में विचार किया जा सकता है। उस मामले में, प्रतिवादियों ने अपनी मिल को वॉलर की आपूर्ति करने के लिए, अपनी जमीन पर एक जलाशय का निर्माण किया था। जिस स्थान को जलाशय के लिए चुना गया था, वहां कोयला खदान के कुछ शाफ्ट मौजूद थे जो उपयोग में नहीं थे। हालाँकि, ये रास्ते निकटवर्ती खदान की ओर भी जाते थे जिसका स्वामित्व वादी के पास था। हालाँकि, निर्माण के समय इसकी खोज नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप जब जलाशय भरा गया, तो पानी शाफ्ट तक चला गया और वादी की खदान में बाढ़ आ गई। इन तथ्यों के तहत,*वादी ने क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर किया और सफल हुआ। प्रतिवादियों की अपील को खारिज करते हुए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा:

> *"इसलिए कानून का सवाल उठता है कि कानून उस व्यक्ति पर क्या दायित्व डालता है, जो प्रतिवादियों की तरह, कानूनी तौर पर अपनी जमीन पर कुछ लाता है, जो कि वहां रहते हुए हानिरहित है, लेकिन अगर वह उसके पास से निकल जाता है तो स्वाभाविक रूप से शरारत करेगा। भूमि? सभी हाथों से इस बात पर सहमति हुई कि जो कुछ वह भूमि पर लाया है और उसे वहीं बनाए रखने का ध्यान उसे रखना चाहिए, ताकि वह भाग न जाए और उसके पड़ोसियों को नुकसान न पहुंचे; लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में कानून उस पर जो कर्तव्य डालता है, उसे अपने जोखिम पर रखना एक परम कर्तव्य है या इसे बनाए रखने के लिए सभी उचित और विवेकपूर्ण सावधानियां बरतना मात्र एक कर्तव्य है, लेकिन अब और नहीं.. .*
>
> *हम सोचते हैं कि कानून का सच्चा नियम यह है कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्यों के लिए अपनी भूमि पर लाता है और वहां कुछ भी इकट्ठा करता है और रखता है जिससे कि अगर वह बच जाता है तो उसे अपने जोखिम पर रहना होगा, और यदि वह ऐसा नहीं करता है। प्रथम दृष्टया*

सभी क्षति के लिए उत्तरदायी है जो इसके भागने का स्वाभाविक परिणाम है। वह यह दिखा कर स्वयं को क्षमा कर सकता है कि पलायन वादी की चूक के कारण हुआ था; या, शायद, कि पलायन 'विज़ मेजर' या ईश्वर के कार्य का परिणाम था; लेकिन चूंकि इस तरह का कुछ भी यहां मौजूद नहीं है, इसलिए यह पूछना अनावश्यक है कि कौन सा बहाना पर्याप्त होगा, " (जोर देने के लिए रेखांकित करना)

(31) सुरेश कुमार (सुप्रा) मामले में, केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 11 केवी लाइन के बिजली के तार के संपर्क में आने पर एक बच्चे को लगी चोटों के लिए मुआवजे के एक मामले की सुनवाई करते हुए, लगी चोटों के लिए मुआवजे के फैसले को बरकरार रखा। मामले के तथ्य यह थे कि 11 केवी लाइन को पकड़ने वाले बिजली के खंभे को सहारा देने वाला एक स्टे वायर घटना से दो दिन पहले प्रतिवादी-बोर्ड के कुछ श्रमिकों द्वारा काट दिया गया था। नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे पोल झुक गया और तार झूल गयाधान के खेत से लगभग एक मीटर की ऊंचाई पर, बच्चा तार के संपर्क में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और जल गया, जिससे उसका दाहिना हाथ कोहनी के नीचे से कट गया।

(32) स्वीट और मैक्सवेल द्वारा टॉर्ट पर विनफील्ड और जोलोविज़ के 11वें संस्करण में, इसे विद्वान लेखकों द्वारा पृष्ठ 352 और पृष्ठ 889 पर निम्नानुसार देखा गया है: -

"बिजली, एक खतरनाक चीज़ है और परिणामस्वरूप जो लोग इसके मालिक हैं या इसे नियंत्रित करते हैं उनका कर्तव्य रायलैंड्स बनाम फ्लेचर ((1868) एलआर 3 एचएल 330) में निर्धारित है। बिजली के लिए दायित्व बिल्कुल गैस के समान ही है।

बिजली के लिए दायित्व गैस के समान ही है। यह निर्णय लिया गया है कि रायलैंड्स बनाम फ्लेचर ((1868) एलआर 3 एचएल 330) का सिद्धांत बिजली पर लागू होता है, और परिणामस्वरूप तारों या केबलों के मालिकों जिनके माध्यम से विद्युत प्रवाह गुजर रहा है, उन्हें अपने जोखिम पर अहानिकर रखना चाहिए। "

(33) यूपी राज्य विद्युत परिषद बनाम चंद्र पाल मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रांसमिशन तारों की उचित ऊंचाई बनाए रखने में विद्युत बोर्ड की विफलता एक लापरवाहीपूर्ण कार्य था और रेस इप्सा लोकिटूर का सिद्धांत लागू था। केवल एक नोटिस या खतरे का संकेत लगाने से बोर्ड को लगी चोटों या मृत्यु के लिए अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएगा। इस तनाव में, बिजली के झटके के मामले भी देखें; जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम मोहम्मद इकबाल, श्रीमती औंगुरी देवी बनाम हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (पी एंड एच) (डीआर), मुश्ताक अहमद बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, रमेश सिंह पवार बनाम एमपीईआर (एमपी), परमजीत कौर बनाम पंजाब राज्य (पी एंड एच) (डीई), दानो राय बनाम पंजाब राज्य, (पी एंड एच) (डीआर), माया रानी रानिक बनाम त्रिपुरा राज्य, (गौहाटी) (डीआर), और यूपी पावर

कॉर्पोरेशन बनाम रिजेंद्र सिंह, आदि।

(34) उपरोक्त मामले के कानून को पढ़ने पर इस मामले में वास्तविक प्रश्न जो मेरे मन में उठता है वह यह है कि क्या बिजली आपूर्तिकर्ता यह दिखाकर खुद को माफ कर सकता है कि याचिकाकर्ता के डिफ़ॉल्ट के कारण पलायन हुआ था। हालाँकि, सख्त दायित्व से उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दों पर थोड़ा संदेह है; जानबूझकर या आश्चर्य से चोट पहुंचाने वाली संभावित खतरनाक चीज़ से बचने के सबूत का बोझ; लाइसेंसधारी से अपेक्षित देखभाल का मानक जो निर्दिष्ट तरीके से कुछ कार्यों और चीजों को करने के लिए अधिनियम और नियमों के तहत वैधानिक रूप से चौकस है; रिट क्षेत्राधिकार में उचित मामलों में मुआवजा देने और मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के संबंधित मुद्दे के लिए इस अदालत का अधिकार क्षेत्र, ताकि यह न तो मुआवजे के तहत हो और न ही अधिक मुआवजे आदि के तहत; वर्तमान मामले में ऐसे कारक घायलों के पक्ष में झुकते हैं और हमें हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। याचिका में किया गया दावा एक कार्रवाई योग्य दावा है और यह मामला संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुआवजा देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।

(35) कानूनी मुद्दे निपटाए गए; न्यायालय की एकमात्र चिंता यह है कि इस मामले में किस हद तक राहत दी जाए। एक नाबालिग के मामले में किन मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए जिसका भविष्य ही अंधकारमय और अनिश्चितता से भरा हुआ है? नाबालिग बच्चे के मामले में आय की हानि, संपत्ति की हानि, भविष्य में रोजगार की संभावना आदि के सिद्धांत अमूर्त रहते हैं।

(36) मोटर दुर्घटनाओं के मामलों में, मुआवजे का मुद्दा मोटे तौर पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 से जुड़ी दूसरी अनुसूची की शुरूआत से पहले और बाद में, और निरस्त 1937 अधिनियम के तहत केस कानून द्वारा विकसित किया गया है और इसमें निर्दिष्ट गुणक के अनुसार मुआवजा दिया गया है। केस-टू-केस आधार पर शेड्यूल करें. इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण मामले महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेन्द्रम बनाम सुसम्मा थॉमस (श्रीमती) और अन्य से संबंधित हैं। (19), सा रिया दीक्षित (श्रीमती) और ए नं. बनाम बाल चाहते हैं यादव और अन्य। (20), यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य। बनाम त्रिलोक चंद्र और अन्य। (21), कौशनुमा बेगम (श्रीमती) और अन्य। बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। (22), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। बनाम पेट्रीसिया जीन महाजन और अन्य। (23), ज्योति कौल एवं अन्य। बनाम मप्र राज्य एवं अन्य। (24),अबाती हेजबरूआ बनाम उप. महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं ए.एन.आर. (25), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शांति पाठक (श्रीमती) और अन्य। (26).

(37) सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2009 के सीए नंबर 4646 (रेशमा कुमारी और अन्य बनाम मदन मोहन और अन्य बनाम 2.4.2003 को तीन जजों की बेंच द्वारा दिए गए एक व्यापक फैसले में मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवजे के मुद्दे पर विचार किया है। आरएम लोढ़ा, जे) बेंच की ओर से बोलते हुए, फैसले के पैराग्राफ 40 में इस विषय पर कानून का सारांश दिया गया है, जो इस प्रकार है: -

"40. हमने ऊपर जो चर्चा की है, उसमें हम अपने निष्कर्षों को इस प्रकार सारांशित करते हैं:

(i) मृत्यु के मामलों में 1988 अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए किए गए आवेदनों में, जहां मृतक की उम्र 15 वर्ष और उससे अधिक है, दावा न्यायाधिकरण सरला वर्मा द्वारा तैयार की गई तालिका के कॉलम (4) में दर्शाए अनुसार गुणक का चयन करेगा। नोट: सरला वर्मा बनाम डीटीसी, (2009) 6 एससीसी121} उस फैसले के पैरा 42 के साथ पढ़ें।

(ii) ऐसे मामलों में जहां मृतक की उम्र 15 वर्ष तक है, धारा 166 या धारा 163 ए के बावजूद, जिसके तहत मुआवजे का दावा किया गया है, 15 का गुणक और दूसरी अनुसूची में बताए गए अनुसार मूल्यांकन, जैसा कि बताया गया है, सुधार के अधीन है। सरला वर्मा की तालिका के कॉलम (6) का अनुसरण किया जाना चाहिए।

(iii) उपरोक्त के परिणामस्वरूप, मृत्यु के मामलों में धारा 166 के तहत किए गए दावा आवेदनों पर विचार करते समय, जहां मृतक की उम्र 15 वर्ष से अधिक है, दावा न्यायाधिकरणों को मार्गदर्शन लेने या दूसरी अनुसूची पर भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1988 अधिनियम.

(iv) दावा न्यायाधिकरण मृत्यु के मामलों में मुआवजे के निर्धारण के लिए सरला वर्मा के पैरा 19 में बताए गए कदमों और दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

(v) भविष्य की संभावनाओं के लिए आय में वृद्धि करते समय, ट्रिब्यूनल सरला वर्मा मामले में फैसले के पैराग्राफ 24 का पालन करेगा।

(vi) जहां तक व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्चों के लिए कटौती का सवाल है, यह निर्देशित है कि न्यायाधिकरण आमतौर पर पैराग्राफ में निर्धारित मानकों का पालन करेंगे सरला वर्मा के मामले में निर्णय के 30, 31 और 32 में की गई टिप्पणियों के अधीन उपरोक्त पैरा 38 में हमारे द्वारा।

(vii) उपरोक्त प्रस्ताव यथोचित परिवर्तनों के साथ सभी लंबित मामलों पर लागू होंगे जहां उपरोक्त पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

(38) चूंकि वर्तमान मोटर दुर्घटना का मामला नहीं है, इसलिए इस मामले के विशेष और विशिष्ट तथ्यों में मुआवजे की मात्रा का निर्धारण किसी सीधे जैकेट फॉर्मूले के अधीन नहीं किया जा सकता है। गुणक/गुणक प्रणाली पर आधारित सूत्र इस मामले में न्यायालय का मार्गदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन मोटर दुर्घटनाओं में न्यायालयों द्वारा विकसित मुआवजे के व्यापक और अंतर्निहित सिद्धांत न्यायालय के लिए मार्गदर्शन बने रहेंगे। बिजली से मौत के मामलों में, न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मुआवजा दे सकता है। हालाँकि, जिन विभिन्न शीर्षों के तहत मुआवजा दिया जा सकता है, वे मोटे तौर पर न्यायिक मिसालों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिनमें मोटर दुर्घटना में मृत्यु या चोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में या बिजली के संपर्क के कारण बिजली के झटके के मामले में मुआवजे का पुरस्कार शामिल है। तार और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें।

(39) मैं श्री मल्होत्रा से सहमत हूं कि बिजली के झटके से हुई चोट की भयावहता के मामले में यह

एक अनोखा और अनोखा मामला है, जो विशेष मुआवजे और क्षति के पुरस्कार के लिए बिल्कुल उपयुक्त मामला है। हालाँकि मैं अलग-अलग मदों के तहत मुआवज़े की उनकी मात्रा के निर्धारण से सहमत नहीं हूँ, जो कि रूढ़िवादी है और न्यायालय की अंतरात्मा या चोट की सीमा को संतुष्ट नहीं करता है, मैं यह सोचने में इच्छुक हूँ कि सख्त दायित्व के सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 21 पर चलते हैं। भारत और हमारे लोगों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए लड़ाई में युद्ध के मैदान पर आक्रमण, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के दृष्टिकोण से देखने पर निगम की ओर से आपराधिक लापरवाही का एक तत्व भी है। विद्युत नियम 1956 के नियम 29,44,45,46 और 91 के साथ मैं यह कहने का साहस करता हूं कि निगम के एजेंटों और सेवकों द्वारा आवधिक या निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। 30 साल पहले सक्रिय ट्रांसमिशन लाइनें खींचने वाला निगम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकता और न ही कोई गलती का दावा कर सकता है क्योंकि निर्माण गतिविधि गांव की लाई लकीर या फिरनी से आगे तक फैल गई है। निगम का यह भी मामला नहीं है कि उसने 11 केवी ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के निवासियों या याचिकाकर्ता के माता-पिता को मीटर के माध्यम से वैध घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं दिए हैं। यदि उन्होंने कनेक्शन दिया है और मीटर लगाए गए हैं और वे बिल के माध्यम से टैरिफ लेते हैं तो वे अनधिकृत निर्माण की शिकायत नहीं कर सकते। आगे,यहां तक कि यह तर्क देते हुए कि याचिकाकर्ता के पिता का संभावित रूप से आक्रामक विद्युत तार को दूर रखने के लिए एंगल आयरन लगाने में हाथ था, उन्हें आत्म-संरक्षण के कार्य के रूप में ऐसा करना समझा जाना चाहिए, यह मनुष्य और उसकी जन्मजात प्रवृत्ति के समान ही आदिम प्रवृत्ति है। जिंदा रहने की चाहत. इसे आपराधिक कानून में निजी बचाव के अधिकार के समान भी देखा जा सकता है। निगम से मदद के अभाव में और खुद को और अपने परिवार को नुकसान से बचाने के लिए कोई भी उचित व्यक्ति तदनुसार कार्य कर सकता था। इसे अपने आप में मुआवज़े के उचित दावे को विफल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालाँकि, इसके विपरीत, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कोई विशिष्ट खंडन नहीं है, कि एंगल आयरन (पी-4) 2006 में निगम के एजेंटों द्वारा स्थापित किया गया था। इस प्रकार सख्त दायित्व और अपकृत्य में लापरवाही की सीमाएँ एक साथ जुड़ जाती हैं और चलती हैं निगम के खतरे के अनुरूप।

(40) इस मामले में, पहला ध्यान निश्चित रूप से कृत्रिम या कृत्रिम/रोबोटिक अंगों सहित रमन के तत्काल चिकित्सा उपचार पर है ताकि बच्चा जल्द से जल्द घूमने और अपने दैनिक काम करने और जीवित रहने के कार्यों को करने में सक्षम हो सके और इसे वास्तविक बना सके। उसके लिए निकटतम स्कूल में दाखिला लेना ताकि उसकी शिक्षा प्रभावित न हो या बाधित न हो। इसके बाद ध्यान 100% स्थायी विकलांगता की पृष्ठभूमि में रमन के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और कुछ व्यवसायों के माध्यम से उसे रोजगार योग्य बनाने का प्रयास करने पर केंद्रित होगा जो उसकी स्थिति के अनुरूप और संभव हो सकता है। इस बात पर भी बड़ा सवालिया निशान है कि क्या रमन को वयस्क होने के बाद अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए रोजगार मिलेगा। एक पैर बचा हुआ है और तीन अंग कटे हैं और स्टंप तीन जोड़ों के ठीक नीचे हैं, कृत्रिम या कृत्रिम अंग रोबोटिक तकनीक के बिना मुश्किल हो सकते हैं, जो शायद बहुत महंगा हो सकता है और निश्चित रूप से रमन का परिवार कभी भी वहन करने में सक्षम नहीं होगा। भविष्य में, स्टेम सेल

थेरेपी/प्रौद्योगिकी रमन के लिए एक वास्तविकता बन सकती है, जो वर्तमान में पाँच वर्ष से थोड़ा अधिक का है। उसके जीवन काल के दौरान कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो उसे मुक्त कर सकता है, लेकिन ये वर्तमान में अपरिहार्य हैं लेकिन निकट भविष्य को देखते हुए राहत देने के लिए अदालत को वर्तमान में विचार करने के लिए निश्चित रूप से कारक हैं। असल में सवाल यह है कि आज उसके भविष्य की रक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। जो कुछ हुआ है उसे कोई भी मुआवज़ा पूरा नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता पूरी तरह से विकलांग है जो अपनी शारीरिक मेहनत से जीवित नहीं रह सकता। वह अपना पेट नहीं भर सकता. वह अपने निकटतम परिवार के सीमित वित्तीय और भावनात्मक संसाधनों पर एक बड़ा बोझ बन सकता है। माँ का प्यार ही एकमात्र आशा हो सकती है, लेकिन वह भी आवश्यक कठिन देखभाल के लिए कम हो सकती है और हर दिन के जीवन के लिए आवश्यक निरंतर सहायता को पूरा करने के लिए वास्तव में पर्याप्त सहायता नहीं हो सकती है। उसका विशेषउसके दो बच्चों में से एक के लिए किए गए श्रम की भरपाई दिन-ब-दिन नर्सिंग देखभाल में शामिल आंशिक व्यय के लिए धन के रूप में करने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक संसाधनों के भीतर से चौबीस घंटे की निगरानी संभव नहीं हो सकती है। याचिकाकर्ता द्वारा विषम समय में मदद की गुहार लगाने से माता-पिता और भाई-बहन का ध्यान नहीं भटक सकता है, जो अपना जीवन जीने में भी शामिल हैं। कौन जागेगा और प्रकृति की पुकार, भूख, भोजन, पानी आदि की पुकार का हमेशा के लिए जवाब देगा जब तक यह रहेगी। स्वच्छता और स्नान भी गंभीर और प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसे दिन-प्रतिदिन कौन करेगा? नहीं, परिस्थितियों में जीवन को यथासंभव सहनीय बनाने के लिए भुगतान पर बाहरी मदद के बिना यह प्रभावी ढंग से संभव नहीं हो सकता है। इस मामले में सभी और विविध लोगों की हताशा स्पष्ट है। निश्चित रूप से, काफी खर्च करके बाहरी मदद लेनी होगी, जो वर्तमान में दिन में आठ घंटे के लिए प्रति माह 7,000/- रुपये से लेकर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक के काम के लिए लगभग 10,000/- रुपये तक हो सकती है। जिसका न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है। याचिकाकर्ता को पूरे जीवन भर, पूरे दिन पारिवारिक सहायता उपलब्ध नहीं हो सकेगी। मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता की जीवन भर देखभाल के लिए भुगतान किए गए देखभालकर्ताओं पर होने वाले व्यय के लिए स्थायी आधार पर कम से कम 15,000/- 17,000/- रुपये प्रति माह शामिल होंगे। कामकाजी दिन के कम से कम एक तिहाई हिस्से में शामिल काम के लिए मजदूरी के संदर्भ में मां के श्रम को भी मात्राबद्ध किया जा सकता है, भविष्य में रोजगार के नुकसान पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। एक दिन याचिकाकर्ता को अपना जीवन बचाने के लिए अकेला छोड़ दिया जाएगा और वह अकेले ही साधारण कामकाज और ऐसी चीजें करने की कोशिश करेगा, जिनका शारीरिक रूप से सुविधा संपन्न लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि केवल पर्याप्त मौद्रिक शुरुआत ही वर्तमान और निकट भविष्य में शारीरिक विकलांगता की विशालता को सबसे अच्छी तरह से पूरा कर सकती है। यदि वर्तमान में इस न्यायालय के हस्तक्षेप से याचिकाकर्ता का ध्यान नहीं रखा गया तो उसे वास्तव में कभी भी उचित मुआवजा नहीं दिया जा सकेगा। यदि याचिकाकर्ता को निगम के विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए मुकदमे के नागरिक उपचार से वंचित कर दिया जाता है, तो वह अकेले देरी से बर्बाद हो जाएगा।

(41) परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और कम-मुआवजा और अधिक-मुआवजा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, यह न्यायालय, अपने सुविचारित दृष्टिकोण से, मौद्रिक मुआवजे, क्षति और

अन्य सहायक और आकस्मिक मामलों की मात्रा निर्धारित करने में निम्नलिखित निर्देश जारी करता है, जैसे: न्याय के लक्ष्य को सुरक्षित करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है:-

(1) प्रतिवादी-निगम राज्य और हरियाणा राज्य का लाइसेंसधारी होने के नाते इस आदेश के तहत दिए गए मुआवजे के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी रहेगा।

(ii) प्रतिवादी लाइसेंसधारी का प्रतिनिधित्व करने वाले इंजीनियर-इन-चीफ या उनके नामांकित व्यक्ति और स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, हरियाणा या रमन के प्राकृतिक माता-पिता के साथ राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके नामांकित व्यक्ति मौद्रिक निष्पादन के उद्देश्य से नाबालिग रमन के संयुक्त संरक्षक होंगे। इस आदेश का मुआवजा और प्रशासन।

(iii) निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले इंजीनियर-इन-चीफ तुरंत स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, हरियाणा के साथ गठजोड़ करेंगे ताकि नाबालिग रमन के तत्काल चिकित्सा उपचार के मामले पर विचार किया जा सके ताकि उसे कृत्रिम अंगों आदि के माध्यम से मोबाइल बनाया जा सके। रमन के पिता को इसमें शामिल किया जाएगा। नाबालिग को उसके माता-पिता, भाई-बहन और अन्य लोगों पर यथासंभव कम निर्भर बनाने के लिए तत्काल समाधान खोजने की प्रक्रिया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, हरियाणा प्रक्रिया शुरू करेंगे और नाबालिग के चिकित्सा उपचार के निष्पादक बने रहेंगे और जब भी देय हो निगम द्वारा भुगतान किए जाने वाले व्यय को प्रमाणित करेंगे। उपचार की दिशा में सिफारिशें करने के लिए पीजीआई, रोहतक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ और एम्स, नई दिल्ली और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सा संस्थानों से परामर्श लिया जा सकता है। इस आदेश में उन संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे नाबालिग रमन की हर संभव मदद करने के उद्देश्य से मानवीय सिद्धांतों पर अपनी विशेषज्ञता स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, हरियाणा के साथ निःशुल्क साझा करें।

(iv) वर्तमान में और भविष्य में नाबालिग के लिए कृत्रिम/रोबोटिक अंग आदि सुरक्षित करने में किए गए सभी खर्च, जिसमें स्टेम सेल तकनीक/थेरेपी भी शामिल है, यदि जीवनकाल के दौरान कोई वास्तविकता है, को महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा द्वारा प्रभावी परामर्श से प्रमाणित किया जाएगा। लालफीताशाही से बचने के लिए निदेशक पीजीआई रोहतक या उनके नामांकित व्यक्ति और प्रतिवादी निगम द्वारा इस आदेश के तहत भुगतान किया गया।

(v) नाबालिग रमन के वित्तीय और मौद्रिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, यह निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी-निगम उसे जीवन के आनंद की हानि, आघात सहने और उपेक्षा के खिलाफ एक रक्षक के रूप में कार्य करने के लिए तुरंत 30 लाख रुपये का मुआवजा देगा। और दूसरों पर निर्भरता, भविष्य की रोजगार क्षमता की हानि और इस सब की पीड़ा, दर्द और मानसिक आघात का सामना करना पड़ा और एक ऐसी अपूरणीय घटना से पीड़ित होना जारी है जिसने एक परिवार

के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर ब्याज सहित उपलब्ध कराई जाने वाली यह राशि भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा और बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करेगी। यह राशि याचिकाकर्ता (नाबालिग) के नाम पर रमन के माता-पिता और प्रतिवादी-निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले उसके नामांकित व्यक्ति के लिए इंजीनियर-इन-चीफ की संयुक्त संरक्षकता के तहत एक राष्ट्रीयकृत बैंक में, अधिमानतः एक सावधि जमा खाते में जमा की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में शाखा। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर बैंक में जमा होने तक राशि पर 8.5% ब्याज लगेगा, जहां मूल राशि के बाद समय-समय पर निर्धारित सावधि जमा के लिए बैंक दरों पर ब्याज मिलेगा। . हालाँकि, इस मद के तहत दी जाने वाली राशि केवल नाबालिग रमन को वयस्क होने यानी 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही मिलेगी। यदि नाबालिग रमन वयस्क होने तक जीवित नहीं रहता है, तो यह राशि सभी अर्जित ब्याज के साथ प्रतिवादी-निगम को वापस कर दी जाएगी और किसी तीसरे पक्ष या रमन के माता-पिता या भाई-बहन द्वारा इस पर कोई दावा नहीं किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बच्चे के वयस्क होने तक उसे महत्व दिया जाए और उसकी देखभाल की जाए।

(vi) चूँकि 30 लाख रुपये की उपरोक्त राशि याचिकाकर्ता के उपयोग के लिए अप्राप्य रहेगी, इसलिए उसे भुगतान किए गए देखभालकर्ताओं/परिचारकों या पारिवारिक सहायता/श्रम के लिए अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए ऐसे खर्चों और अन्य नंगे और विविध खर्चों के बराबर आय की आवश्यकता होगी, जो मात्राबद्ध हैं। वर्तमान में जीवन भर के लिए लगभग रु. 20,000/- से अधिक। प्रति माह 20,000/- रुपये का ब्याज अर्जित करने के लिए लंबी अवधि की सावधि जमा पर मौजूदा दरों के अनुसार 8.5% की दर से ब्याज अर्जित करने के लिए बैंक में 30 लाख रुपये का निवेश करना आवश्यक है। इसलिए, निर्देश (v) में दिए गए 30 लाख रुपये के अलावा, प्रतिवादी-निगम रुपये की अतिरिक्त राशि का मुआवजा देगा और जमा करेगा। 30 लाख रुपये को उसी बैंक में एक अलग ब्याज वाले खाते में रखा जाना चाहिए जैसा कि बिंदु संख्या के तहत निर्देशित है। (v), उसी संयुक्त संरक्षकता व्यवस्था के तहत। यह एक ब्याज अर्जित करने वाला खाता होगा जिसमें याचिकाकर्ता की दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्याज आय उपलब्ध होगी। इस प्रकार अर्जित ब्याज होगानाबालिग रमन के नाम पर उसी शाखा में खोले जाने वाले एक अलग बचत बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसे माता-पिता द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा, जिसे याचिकाकर्ता को नियमित मासिक आधार पर भुगतान करना होगा, जिसे माता-पिता द्वारा बच्चे की देखभाल, उसके शैक्षिक खर्चों के लिए लागू किया जाएगा।

पौष्टिक भोजन, प्रतिदिन उसकी सेवा करने वाले परिचारकों/देखभाल करने वालों की लागत आदि। 30 लाख रुपये की उपरोक्त राशि, जिसमें से याचिकाकर्ता के लिए महीने-दर-महीने ब्याज का उपयोग किया जाएगा, को भी किसी भी उद्देश्य के लिए निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। याचिकाकर्ता के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इस न्यायालय से आदेश प्राप्त किए बिना, यदि परिस्थितियाँ उचित हों, निर्देशानुसार मासिक ब्याज को छोड़कर। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ की स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा माता और पिता की देखरेख में नाबालिग के नाम पर उक्त बचत बैंक खाता खोलेगी और उक्त बचत बैंक खाते को उसके निवास के निकटतम शाखा में स्थानांतरित करेगी। याचिकाकर्ता और बैंक हर महीने उस पर अर्जित ब्याज को पानीपत शाखा में उक्त बचत खाते में भेज देंगे, जो याचिकाकर्ता के 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक स्वत: नवीनीकृत हो जाएगा। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर बैंक में जमा होने तक राशि पर 8.5% ब्याज लगेगा, जहां मूल राशि के बाद समय-समय पर सावधि जमा के लिए बैंक दरों पर ब्याज दिया जाएगा। .

(vii) जिला समाज कल्याण अधिकारी, पानीपत या उनके नामांकित व्यक्ति को याचिकाकर्ता के घर का समय-समय पर दौरा करके उसकी देखभाल और कल्याण के बारे में जानने, टायर विभाग के साथ उपलब्ध किसी भी सहायता की पेशकश करने और समय-समय पर उसके निष्कर्षों की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता के माता-पिता या दोनों में से किसी एक या दोनों के दौरे की पावती प्राप्त करने के बाद यदि आवश्यक हो तो निगम और महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा को उनके रिकॉर्ड और कार्रवाई के लिए भेजें और यदि कुछ और करने की आवश्यकता हो तो। निगम और महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा हरियाणा को तदनुसार सूचित करने के लिए और, यदि आवश्यक हो, तो इस न्यायालय को अगले आदेश के लिए। अभिभावकों की मृत्यु के मामले में, पक्षों को इस आदेश को प्रभावी करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने के लिए उचित आदेश के लिए इस न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता होगी।

(viii) चूंकि उपरोक्त राशियों पर ब्याज घटक आय का गठन करेगा और इसलिए आयकर के लिए पात्र होगा, बैंक जहां राशि जमा होगी, उसे माइनर रमन की ओर से देय कर को माफ करने/टीडीएस काटने के लिए ऐसे सभी कदम उठाने और प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है। याचिकाकर्ता के माता-पिता और प्रतिवादी-निगम को उनके रिकॉर्ड के लिए भुगतान किए गए कर का विवरण। याचिकाकर्ता के माता/पिता आयकर विभाग से एक स्थायी खाता संख्या के लिए

आवेदन करेंगे और प्राप्त करेंगे ताकि ब्याज आय पर 20% की कटौती न हो। यदि याचिकाकर्ता के माता/पिता पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आयकर अधिकारियों को भुगतान की सुविधा के लिए याचिकाकर्ता के माता/पिता के पक्ष में शीघ्रता से पैन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया जाता है, यदि उनके पास पहले से कोई पैन कार्ड नहीं है। नाबालिग की ओर से उसकी आय के हिस्से के रूप में कर का भुगतान। यह आदेश आयकर आयुक्त, हरियाणा सर्कल, हरियाणा को पैन कार्ड और कर निहितार्थ के प्रयोजनों के लिए इस आदेश के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए, यदि कोई हो, भेजने के लिए निर्देशित किया जाता है।

(ix) प्रतिवादी-निगम नाबालिग रमन की मृत मां को उसके, मामूली घायल बच्चे और परिवार के सदस्यों को हुए आघात, मानसिक आघात, दर्द और पीड़ा के लिए तुरंत 2 लाख रुपये का मुआवजा देगा।

(x) याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता के पिता को देय 20,000/- रुपये की मुकदमेबाजी लागत का भी हकदार होगा।

(xi) भविष्य में, जब नाबालिग रमन रोजगार योग्य उम्र में आ जाता है और यदि प्रतिवादी-निगम को पता चलता है कि रमन नियमों के अनुसार किसी भी पोस्टिंग के लिए योग्य है, तो वह रमन को अनुकंपा के आधार पर स्थायी रोजगार की पेशकश कर सकता है। इस आदेश के संदर्भ में अपवाद. यदि निगम द्वारा भविष्य में और 21 वर्ष की आयु तक रमन को स्थायी रोजगार की पेशकश की जाती है, तो निर्देश (v) के तहत इस न्यायालय द्वारा दिया गया 30 लाख रुपये का मुआवजा उसके भविष्य निधि खाते/पेंशन खाते में डाल दिया जाएगा। या नियमों के अपवाद के रूप में या निगम द्वारा उपयुक्त पाए गए किसी भी वैकल्पिक नाम से, या तो एकमुश्त या समय-समय पर, जैसा भी मामला हो और सेवानिवृत्ति पर या रोजगार के दौरान मृत्यु के मामले में अंततः उसके लिए उपलब्ध हो। नामांकित व्यक्ति मेंयदि इस अंतिम निर्देश को क्रियान्वित नहीं किया जाता है, तो वर्तमान निर्देश के तहत इस न्यायालय द्वारा दिया गया 30 लाख रुपये का मुआवजा 21 वर्ष की आयु में वयस्क होने पर रमन को मिलेगा, लेकिन ब्याज के बिना। हालाँकि, आसानी से याचिकाकर्ता वयस्क होने तक जीवित नहीं रहता है तो 25 लाख रुपये, या इस न्यायालय के किसी भी आदेश के परिणामस्वरूप कटौती की गई राशि, निगम को वापस कर दी जाएगी और रुपये। याचिकाकर्ता के माता-पिता दोनों को उनके गंभीर नुकसान, दर्द और पीड़ा, चिकित्सा व्यय सहित बच्चे पर पहले से खर्च किए गए खर्च और भविष्य के आय जनरेटर/रोटी विजेता की हानि के लिए 5 लाख रुपये तत्काल देय होंगे।

(xii) चूंकि इस न्यायालय ने सख्त और प्रतिवर्ती दायित्व दोनों के सिद्धांतों पर और लापरवाही के आधार पर कपटपूर्ण दायित्व पर पर्याप्त मौद्रिक मुआवजा दिया है, इसलिए यह आदेश दिया गया है कि कोई भी नागरिक मुकदमा किसी भी न्यायालय में आगे मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

(xiii) निगम को यह निर्देश भी जारी किया गया है कि आबादी के ऊपर 11 केवी ट्रांसमिशन लाइनों की ऊंचाई तुरंत बढ़ाई जाए ताकि इसे सुरक्षित बनाया जा सके और उन्हें आबादी के लिए विद्युत रूप से हानिरहित बनाया जा सके और उन्हें नीचे के आदमी की पहुंच से परे ले जाया जा सके या ऐसा कोई उपाय किया जा सके। अन्य विकल्प ताकि शुरुआत में गांव सनोली खुर्द, जिला पानीपत में कॉलोनी को पूरी तरह से बायपास किया जा सके।

(42) उपरोक्त कारणों से, इस याचिका को उपरोक्त निर्देशों और टिप्पणियों के साथ अनुमति दी जाती है और इसे निपटाया जाता है, हालांकि, पार्टियों को वर्तमान मामले में किसी अन्य या आगे के निर्देश की तलाश करने की स्वतंत्रता है जिसके लिए समय बीतने की आवश्यकता हो सकती है और जो है फिलहाल अनुमान नहीं है.

(43) हस्ताक्षर करते समय, यह न्यायालय इस विषय पर विद्वान न्याय मित्र श्री अनिल मल्होत्रा द्वारा लाई गई स्पष्टता पर अपनी सराहना दर्ज करता है और इस निर्णय में परिशिष्ट 1 और 2 संलग्न करने का सुझाव देने के लिए मेरे सचिव श्री एमई खान को भी धन्यवाद देता है। इसे आत्मनिर्भर और व्यापक बनाना और निगम को एक नज़र में अक्षमता की भयावहता और आगे आने वाली समस्याओं का एहसास कराना, जिसके लिए वास्तव में कोई भी मौद्रिक संशोधन पर्याप्त नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

विनीत कुमार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
झज्जर, हरियाणा